सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-32 अंक-08 | 22 अप्रैल से 6 मई, 2017 | मुख्य संपादक : कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ 8 | मूल्य : 2 रुपये

साझे आन्दोलनों को मजबूत करें, सही दिशा में आगे बढ़ायें महान मई दिवस का आह्वान

पहली मई को 131वां अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। यह ऐतिहासिक मई दिवस हर साल हमें अपने हकों व न्याय के लिये आवाज बुलन्द करने, आपसी भाईचारा मजबूत करने और पूंजीवादी शोषण-अन्याय-जुल्म के जाल को तोड़ डालने के लिए साझे संघर्ष का दृढ़ संकल्प लेने की याद दिलाता है। इस के क्रान्तिकारी मायने समझना अत्यन्त जरूरी है।

ऐतिहासिक मई दिवस की सीख : मई दिवस का इतिहास गौरवशाली कुर्बानियों व वीरतापूर्ण संघर्षों की सीख देता है। पूंजीपति कारखानेदार और उनके पैरोकार बातें तो न्याय, बराबरी, आजादी व जनतन्त्र की करते हुए थकते नहीं परन्तु अधिकतम मुनाफा निचोड़ने के लिए मजदूरों से गुलामों जैसा बर्ताव करते हैं। पहले रोजाना 12 घण्टे से भी ज्यादा काम लिया जाता था। इसके खिलाफ महान कार्ल मार्क्स ने रोजाना 8 घण्टे का कार्यदिवस न्यायसंगत बताया था और 'दुनिया के मजदूरो एक हो' का संघर्ष-घोष दिया था। तभी से देश-देश में 8 घण्टे के कार्य-दिवस के लिए मांग उठनी शुरू हुई। इस मांग पर 1862 में भारत में भी हावड़ा के 1200 रेलवे मजदूरों ने हड़ताल की थी। 1886 में अमेरिका में भी 8 घण्टे का कार्यदिवस करने की मांग उठी। वहां 1 मई 1886 को सफल हड़ताल हुई। इससे पूंजीपति वर्ग बौखला उठा। 4 मई को जब शिकागो शहर के हे-मार्केट चौक में मजदूर शान्तिपूर्ण सभा कर रहे थे तब उन पर पुलिसिया दमन चक्र चलाया गया। मजदूरों के बहे खून से झण्डा लाल हो गया। कई मजदूर घायल हुये, बहुत सारे गिरफ्तार कर लिए गये और झूठे केस बनाकर 4 मजदूर नेताओं को फांसी की सजा दी गई। शिकागो की इस घटना ने अमेरिका में 'जनतंत्र' व 'आजादी' के लम्बे चौड़े दावों की पोल खोल दी और पूंजीवाद के क्रूर व घिनौने चेहरे से नकाब हटा दिया।

मई दिवस के महत्व को दर्शाते हुए विश्व के महान् क्रान्तिकारी नेता, शिक्षक व पथ-प्रदर्शक फ्रेडरिक एंगेल्स ने 1890 से पहली मई का दिन सारी दुनिया में मजदूर-दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि, *''एक तरफ दुनिया भर के सर्वहारा-मजदूरों का खेमा है जो सर्वत्र मुक्ति के झण्डे तले जीत की तरफ लम्बे डग भर रहा है, दूसरी तरफ पूंजीपतियों, धनवानों व प्रतिक्रियावादियों ने शोषण (कायम रखने) के लिए हाथ मिला लिये हैं। इन दोनों खेमों के बीच संघर्ष शुरू हो चुका है...जीत आपकी होगी-आगे बढ़ो।''*

इतिहास गवाह है- दुनिया भर में बड़े-बड़े मजदूर आन्दोलन हुए। भारत समेत हर देश में 8 घण्टे के कार्यदिवस को कानूनी मान्यता मिली। सौ साल पहले 1917 में मजदूर वर्ग के नेतृत्व में रूस में महान नवम्बर क्रान्ति हुई। वहां पूंजीवाद को उखाड़ फेंक कर शोषणहीन समाज, समाजवाद कायम हुआ था। मानव के द्वारा मानव के शोषण का वहां खात्मा हो गया था। इसके बाद कई अन्य देशों में भी समाजवाद आया था। मजदूरों को रोजगार का संवैधानिक अधिकार मिला था जो आज तक कोई पूंजीवादी देश नहीं दे पाया है। **(शेष पृष्ठ 2 पर)**

सीरिया पर अमेरिकी साम्राज्यवादी हमले की एसयूसीआई (सी) ने की निंदा

7 अप्रैल 2017 को एसयूसीआई (सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने निम्नलिखित बयान जारी किया :

अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा सीरिया पर आज का यह घिनौना और वहशियाना हमला इस बात की मुँह बोलती मिसाल है कि किस प्रकार जंगखोर साम्राज्यवाद, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद राष्ट्रों की सम्प्रभुता को रौंद रहा है और मानव जाति व सभ्यता के खिलाफ मानवविरोधी नीतियाँ लागू कर रहा है। मैं तमाम सच्चे शांतिप्रिय लोगों से आगे आने और एकजुट खड़ा होने की अपील करता हूँ ताकि दुनिया भर में साम्राज्यवाद-विरोधी जुझारू आन्दोलन संगठित करते हुए अमेरिकी साम्राज्यवाद की इस घिनौनी साजिश को नाकाम किया जा सके।

कोलकाता : विरोध प्रदर्शन करते हुए एसयूसीआई(सी) कार्यकर्ता

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान एकता के लिए खतरा – एसयूसीआई(सी)

10 अप्रैल 2017 को एसयूसीआई (सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने निम्नलिखित बयान जारी किया :

गौ-वध पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने और इसके अनुपालन को अधिक प्रभावकारी ढंग से सुनिश्चित करने के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आग्रह पर चिंता व्यक्त करते हुए 10 अप्रैल 2017 को जारी बयान में एसयूसीआई (सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने कहा कि हमारे जैसे बहुधर्मीय, बहुभाषी एक देश में जिसे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक देश के रूप में देखा था, ऐसा एक कदम गंभीर खतरे और परिणामों का सबब बन सकता है। जाति, धर्म, सम्प्रदाय और भाषा का लिहाज किये बिना सभी भारतीय नागरिकों की एकता की जड़ पर निश्चित ही प्रहार करने वाला कदम करार देते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि गंभीर प्रकृति का यह विभेद सामाजिक ताने-बाने को ही तबाह कर देगा जो हमारे देश के अस्तित्व और महान और उदात्त राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए अत्यावश्यक है। इसके लिए तमाम मानव अधिकारों, धर्मनिरपेक्ष जनवादी मूल्यबोधों और उच्च संस्कृति को मजबूती से बुलंद रखना जरूरी है। इसलिए हम शिद्दत के साथ महसूस करते हैं कि इस घोर विनाशकारी विचार को तुरंत त्याग देना चाहिए। देशभर के सभी सही सोच रखने वाले लोगों और तमाम धर्मनिरपेक्ष जनवादी पार्टियों से भी एकजुट हो जाने और ततकाल कदम उठाने की मांग करते हैं ताकि आरएसएस द्वारा प्रस्तुत इस घातक विचार को तुरंत छोड़ा जा सके।

मारुति मजदूरों को न्याय दिलवाने के लिए विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा

5 अप्रैल को मारुति मजदूरों पर हो रहे अन्याय के विरोध में और श्रम अधिकारों की हिमायत में मजदूरों व उनके परिवारों के प्रति एकजुटता का इजहार करते हुए केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों सीटू, एटक, इंटक व एआईयूटीयूसी और कर्मचारी संगठनों, सर्व कर्मचारी संघ, कर्मचारी महासंघ व संयुक्त कर्मचारी मंच द्वारा रोहतक, झज्जर, सोनीपत, हिसार, भिवानी, कैथल, जीन्द आदि हरियाणा के लगभग सभी जिलों में रोष मार्च निकालते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए। दिल्ली में हरियाणा भवन पर रोष मार्च निकाला गया। श्रमिक नेताओं ने कहा कि हुड्डा सरकार के कार्यकाल में 18 जुलाई 2012 को गुड़गांव स्थित **(शेष पृष्ठ 7 पर)**

दिल्ली: हरियाणा भवन पर प्रदर्शन करते हुए ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ता

एसयूसीआई (सी) नेताओं की बिना शर्त रिहा करने की मांग को लेकर केरल सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए एसयूसीआई (सी) कार्यकर्ता

मई दिवस का आह्वान ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

शोषणकारी पूंजीवादी व्यवस्था ही है सब समस्याओं की जड़ : पूंजीवादी शोषण से मुक्ति की जो चाह मई दिवस के संघर्ष से व्यक्त हुई थी, वह आज भी अधूरी है। पूरी दुनिया में पूंजीवादी-साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था भयंकर मंदी की चपेट में है। अपने संकट का सारा बोझ यह मेहनतकश जनता पर डालती जा रही है। हर जगह मजदूरों पर असहनीय जुल्म-अत्याचार हो रहे हैं। अधिकतम मुनाफा लूटना आम नियम बन गया है। बहुत बड़े पैमाने पर मजदूरों पर काम का बोझ बढ़ाया जा रहा है और उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। भले ही यहाँ 8 घण्टे के कार्य दिवस को कानूनी मान्यता है लेकिन देश-प्रदेश के ज्यादातर उद्योगों व कारखानों में 8 घण्टे का कार्य-दिवस, न्यूनतम वेतन, वेज स्लिप, हाजरी कार्ड, हाजरी रजिस्टर, ई.एस.आई. व पी.एफ. ग्रेच्युटी, पेन्शन जैसे अनिवार्य कानूनी प्रावधान लागू नहीं हैं। याद रहे, मजदूरों व कर्मचारियों के हक में बने सभी कानून हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों के फल हैं।

1886 में मजदूरों का जितना शोषण किया जाता था आज उससे कहीं ज्यादा शोषण है। मजदूरों की हालत बन्धुआ गुलामों से भी बदतर है। बड़े संघर्षों से हासिल यूनियन बनाने व हड़ताल करने के जनतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। सन् 2012 से मारूति के 148 मजदूरों को जेल में नाजायज बन्द रखा और अब 13 मजदूरों को उम्र कैद, 4 को 5 साल की जेल की सजा सिर्फ इसलिए मिली है कि वे बेहतर काम के साथ बेहतर वेतन की मांग हासिल करने के लिए अपनी यूनियन बनाने का 'अपराध' कर रहे थे।

पूंजीपतियों की ताबेदार सरकारों द्वारा सन् 1991 से पूंजीवादी भूमण्डलीकरण-उदारीकरण की विनाशकारी नीतियां लागू करके मजदूरों को और भी ज्यादा बंधनों में बांधा जा रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, रेल-रोडवेज आदि सेवा क्षेत्र का निजीकरण-व्यापारीकरण किया जा रहा है। इससे महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लाखों खाली पड़े पद भरे नहीं जा रहे हैं। नई भर्ती पर रोक है। पुरानी पेन्शन स्कीम का बुनियादी हक खत्म करके अंशदान के रूप में वेतन से पैसे काटकर पेन्शन देने की स्कीम शुरू की गई है। पीएफ व ग्रेच्यूटी के पैसों को सट्टे बाजार में लगा कर खतरे में डाला जा रहा है। न्यूनतम वेतन बहुत कम है। स्थायी कामों में भी ठेका प्रथा को बढ़ावा देकर कम तनख्वाह पर काम लिया जाता है। मनमर्जी जब चाहे हटा दिया जाता है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिड डे मील कार्यकर्ता, ग्रामीण चौकीदार और सफाई कर्मचारी सब के सब सरकारी काम करते हैं फिर भी उन्हें न्यायसंगत न्यूनतम वेतन व सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। उल्टे, सोनीपत जिला में 1482 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी से हटाने का नोटिस दिया गया है। उनका कसूर यह है कि वितमन्त्री द्वारा घोषित मेहनताना देने की अपनी चाह उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने प्रकट करने की हिम्मत कैसे की। उन्हें माफीनामा लिखने के लिए बाध्य किया जा रहा है जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका यूनियन की जिला प्रधान व कुछ अन्य को बिना किसी नाटिस के नौकरी से हटा दिया गया है। सर्कस के जीवों की तरह उन्हें अनुशासित बनना सिखाया जा रहा है।

भवन निर्माण कारीगर-मजदूर-मिस्त्रियों के कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराने व हितलाभ पाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है। बहुत सारी नाजायज शर्तें थोंपी हुई हैं। इसलिए बहुत से श्रमिक पंजीकृत ही नहीं हैं। वे बोर्ड से मिलने वाले हितलाभों से वंचित हैं। उनकी दिहाड़ी मार ली जाती है।

श्रम कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने देशी-विदेशी कारपोरेट घरानों की इच्छानुसार औद्योगिक विवाद एक्ट, फेक्ट्री एक्ट, ठेका श्रमिक एक्ट व वेतन भुगतान कानून में घोर मजदूर-विरोधी संशोधन किये हैं। जातपातीय, साम्प्रदायिक ताकतें जोर पकड़ती जा रही है जो मजदूर आन्दोलन में फूट डाल कर समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को तार-तार कर रही हैं। मानव सभ्यता के घोर दुश्मन फासीवाद का खतरा उभर कर आ रहा है।

मुक्ति का रास्ता : याद रखें, पूंजीवादी व्यवस्था के रहते इस असहनीय स्थिति को जरा भी कम नहीं किया जा सकता। मेहनतकशों को पूंजीवाद-विरोधी संघर्ष की राह पर चलने का संकल्प लेना होगा। मजदूर आन्दोलन का नेतृत्व सही दिशा में सही हाथों में होना जरूरी है ताकि मजदूर आन्दोलन को अर्थवाद, संसदवाद, कानूनवाद की भ्रान्तियों से मुक्त किया जा सके जो इसे भीतर से घुन की तरह खा रही हैं। साथ ही धर्म-जातपात-इलाके के आधार पर फूट डालने वाली ताकतों से बचना होगा। इस युग के महान मार्क्सवादी चिंतनकार, भारत के मजदूर आन्दोलन के पथप्रदर्शक, सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष ने आह्वान किया था : *''आप मजदूर... इस सभ्यता के स्रष्टा हैं। आज यह सभ्यता मुक्ति-वेदना से छटपटा रही है, यह चाहती है कि आप इसे मुक्ति दिलाएं। सिर्फ आपकी अपनी मुक्ति ही नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता की मुक्ति आपके हाथ में है।''*

वक्त का तकाजा : देश-दुनिया में हर जगह पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ मेहनतकश लोगों के कहीं स्वत:स्फूर्त, कहीं संगठित विक्षोभ आन्दोलन जोर पकड़ रहे हैं। हमारे देश में भी सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों व कदमों के खिलाफ साझे आन्दोलन के बल पर मजदूरों ने देशव्यापी कई सफल हड़ताल की हैं। मई दिवस आज हमें आन्दोलन की एक नई लहर खड़ी करने के लिए पुकार रहा है। अपनी ज्वलंत मांगों को लेकर साझा आन्दोलन मजबूत बनाने व समाज में आमूलचूल बदलाव के लिए आइये, हम दृढ़ संकल्प लें!

शैक्षणिक समस्याओं पर छात्र कन्वेन्शन आयोजित

जबलपुर: कन्वेन्शन को संबोधित करते हुए कॉ. सचिन जैन

जबलपुर (म.प्र.) : स्थानीय रानी दुर्गावती संग्रहालय के हाल में शहीद-ए-आजम भगत सिंह स्मृति दिवस पर वर्तमान शैक्षणिक, सांस्कृतिक व सामाजिक समस्याओं पर एक कन्वेन्शन 10 अप्रैल को एआईडीएसओ के तत्वावधान में आयोजित किया गया। कन्वेन्शन को सम्बोधित करते हुए संगठन के राज्य सचिव कॉमरेड सचिन जैन ने कहा कि आजादी आन्दोलन की गैर समझौतावादी धारा के क्रान्तिकारी शहीद भगत सिंह ने देश की आजादी की लड़ाई में जो सपना देखा था कि आजादी के बाद आम जनता को मूलभूत सुख-सुविधाएं उपलब्ध होंगी और हर तरह के शोषण से मुक्ति मिलेगी, वह सपना आज भी अधूरा है। आज भी हमारे देश का अधिकांश छात्र तबका सही शिक्षा लेने से वंचित है शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण, सेमेस्टर सिस्टम व 8वीं तक पास-फेल प्रणाली खत्म कर शिक्षा को एक व्यापार की वस्तु में तब्दील कर दिया गया है। इन सब शिक्षा-विरोधी नीतियों के खिलाफ एआईडीएसओ लगातार आन्दोलनरत है। उन्होंने इसे मजबूत करने की अपील की।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जाने-माने शिक्षाविद श्री गार्गीशरण मिश्रा ने कहा कि शिक्षा समाज की रीढ़ का काम करती है। इसलिए शिक्षा आम जन को सर्वसुलभ होनी चाहिए परंतु सरकारी स्कूलों को बंद करने की सरकार की नीति इस रीढ़ को तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को सभी को शिक्षा देने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एआईडीएसओ के राज्य अध्यक्ष मुदित भटनागर ने सभी से अपील की कि आज भगत सिंह जैसे क्रान्तिकारियों और महापुरुषों के विचारों को आत्मसात करें, तमाम जनविरोधी व छात्र-विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार छात्र आन्दोलन गठित करें। कार्यक्रम में एआईएमएसएस की चंद्रा पात्रा भी उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन एआईडीएसओ की राज्य सचिव मण्डल सदस्या बबीता समर ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे।

पूरे सम्मान के साथ मनाया गया शहीद-ए-आजम भगत सिंह शहादत दिवस

दुर्ग (छ.ग.) : 23 मार्च को आजादी आंदोलन के महान क्रांतिकारी शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव शहादत दिवस एआईडीवाईओ व एआईडीएसओ के द्वारा छ.ग. राज्य में राजधानी रायपुर, जिला दुर्ग, बिलासपुर एवं पखान्जूर में पूरे सम्मान के साथ मनाया गया। दुर्ग में शहीद चौंक में कार्यकर्ताओं के द्वारा शहीद-ए-आजम भगत सिंह, शहीद चन्द्र शेखर आजाद, नेताजी सुभाष, शहीद उधम सिंह की मूर्तियों पर फूलमालाएं चढ़ा कर श्रद्धांजली दी गई। वक्ताओं ने उनके जीवन संघर्ष व देश की आजादी आंदोलन में क्रांतिकारियों की भूमिका पर प्रकाश डाला।

शाम को ग्राम जेवरा जिला दुर्ग में छ.ग. राज्य शराब-विरोधी संघर्ष समिति द्वारा जेवरा बाजार में सभा की गई। सभा को सम्बोधित करते हुए कॉ. आत्मा राम साहू ने कहा कि शहीद-ए-आजम भगत सिंह बहादुर, निडर, कर्तव्यपरायण, कुर्बानी और देशभक्ति की बेजोड़ मिसाल पेश कर गये। उनके शहादत दिवस पर उन्हें सम्मान से याद करना, उसके बेमिसाल चरित्र एवं जीवन संघर्ष से सीख लेना हमारे लिए बेहद जरूरी है ताकि वर्तमान में अपना फर्ज निभाने लायक बनने के लिए हम उन्नत नैतिक स्तर हासिल कर सकें। उन्होंने आगे कहा कि आज शहीद-ए-आजम भगत सिंह व उनके जैसे क्रांतिकारियों को भुला दिया जा रहा है। पाठ्य पुस्तकों से इन क्रांतिकारियों की जीवनियों को हटाया जा रहा है। छात्र-युवाओं में तीव्र गति से सांस्कृतिक नैतिक पतन हो रहा है। छात्र-युवाओं को साजिश पूर्ण तरीके से शराबखोरी, अश्लीलता में डूबाया जा रहा है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश की जनता कई समस्याओं से परेशान है। इन क्रांतिकारियों ने सपना देखा था कि आजाद भारत में तमाम तरह के शोषण, उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार समाप्त हो जायेंगे, सभी विद्यार्थियों को नि:शुल्क व समान शिक्षा का अधिकार होगा, गरीबी व बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। किन्तु ऐसा न होकर तमाम समस्याएं विकराल रूप लेती जा रही हैं। इन समस्याओं के समाधान का एकमात्र रास्ता है जोरदार छात्र व युवा आंदोलन। शहीद-ए-आजम भगत सिंह व साथी क्रांतिकारियों के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर इन समस्याओं के समाधान के लिए जोरदार आंदोलन निर्मित करें।

महान नवम्बर क्रान्ति के सौ साल

महान नवम्बर क्रान्ति मानव जाति की मुक्ति के इतिहास में अत्यन्त गौरवोज्जल घटना है। कॉमरेड लेनिन के नेतृत्व में रूस के मजदूर-किसानों ने उन दिनों साबित कर दिया था कि अगर आदर्श ठीक हो, नीति-सिद्धान्त ठीक हो, तो सही क्रान्तिकारी पार्टी के नेतृत्व में मजदूर-किसान अनहोनी को होनी कर सकते हैं, पूंजीपतियों के हमले को नाकाम कर शोषण की तमाम पीड़ा का खात्मा कर सकते हैं, सर्वहारा का अधिनायकत्व, समाजवाद कायम कर सकते हैं। हमारी पार्टी की पहल पर इस वर्ष महान नवम्बर क्रान्ति का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसलिए इसकी कड़ी के रूप में पार्टी की बंगाल राज्य कमेटी की तरफ से 'महान नवम्बर क्रान्ति शतवर्षे' नामक पुस्तिका तैयार की गई है और प्रकाशित की गई है। इस पुस्तिका में महान नवम्बर क्रान्ति की तैयारी के दौर से लेकर उसके सफल होने तक की एक संक्षिप्त रूपरेखा पेश करने की कोशिश की गई है। रूस के समाजवाद के बारे में मार्क्सवादी नेताओं की विभिन्न शिक्षाओं और जाने-माने प्रसिद्ध मानवतावादी चिन्तकों की विभिन्न ध्यान-धारणाओं को पेश करने की कोशिश की गई है। इस पुस्तक को हिन्दी में रूपान्तरित कर प्रकाशित करने की जरूरत बड़ी शिद्दत के साथ महसूस की जा रही थी। यह उसी का हिन्दी अनुवाद है। हम आशा करते हैं कि यह प्रयास नवम्बर क्रान्ति के बारे में एक समग्र धारणा निर्मित करने में सहायक होगा। अनुवाद में या अभिव्यक्ति में रह गई कमी-खामी के लिए पूर्णतया हम जिम्मेदार होंगे। (सम्पादक स. दृ.)

अमीर-गरीब में फर्क क्या कभी मिटेगा! कमजोरों पर बलवानों का अत्याचार क्या कभी बन्द होगा! आदमी-आदमी में समान अधिकार क्या कभी प्रतिष्ठित होगा! ये सवाल हमेशा दुनिया के शोषित-पीड़ित असहाय लोगों के मन में उठे हैं, उन्होंने इन पर सोच-विचार किया है, उस व्यथा-वेदना ने महापुरुषों के दिलों को झकझोरा है। उन्होंने तरह-तरह से इन सब सवालों का जबाव देने की जी-जान से कोशिश भी की। समस्याओं को हल करने की भी कोशिश की। लेकिन उन्हें सही जवाब नहीं मिल पाया। वे समस्याओं को हल नहीं कर पाये। जिस आर्थिक-सामाजिक परिस्थिति में उनका आविर्भाव हुआ था, उस परिस्थिति में इन सब समस्याओं का समाधान सम्भव ही नहीं था। समाज विकास के एक निर्दिष्ट स्तर पर आकर इन सवालों का हल, इन समस्याओं का समाधान सम्भव हुआ। मनुष्य के ज्ञान जगत के सामने यह सच उभर कर आया कि गैर बराबरी का स्रोत वर्ग शोषण है। सिर्फ इस वर्ग शोषण के खात्मे के जरिए ही कमजोरों पर बलवानों का अत्याचार बन्द हो सकता है। अगर उत्पादन के साधनों-उपकरणों पर व्यक्तिगत मालिकाना की बजाय सामाजिक मालिकाना कायम कर दिया जाये, सर्वहारा अधिनायकत्व कायम कर दिया जाये, पूँजीवादी राज्य-व्यवस्था को उखाड़ फेंक कर उसकी जगह समाजवादी राज्य व्यवस्था कायम कर दी जाए तो यह वर्ग शोषण बन्द हो जाएगा। एंगेल्स ने कहा था, "अब तक मनुष्य ने परलोक में स्वर्ग कायम होने की कल्पना की है। हम वह स्वर्ग इसी धरती पर ही कायम करना चाहते हैं।" यहां स्वर्ग कहने से एंगेल्स का अभिप्राय था शोषणहीन समाज व्यवस्था की स्थापना जिसमें मनुष्य हर तरह के शोषण-दमन से मुक्त होने की जरूरत के राज्य से स्वतंत्रता के राज्य में प्रवेश करेगा। मार्क्स-एंगेल्स की बात उन दिनों ज्यादातर लोगों को ही असम्भव लगती थी। वे विश्वास ही नहीं कर सकते थे कि यह सम्भव है। लेकिन रूस की नवम्बर क्रान्ति ने साबित कर दिया कि यह सम्भव है। इस धरती पर ही स्वर्ग कायम किया जा सकता है। ऐसा मजदूर वर्ग कर सकता है। इतिहास की चालक शक्ति के तौर पर उनके कन्धों पर ही यह जिम्मेदारी आ गयी है। यूरोप की औद्योगिक क्रान्ति के जरिए एक नई तरह का नया इन्सान पैदा हुआ था। गांवों से उखाड़ फेंके हुए इन लोगों के पास धन-दौलत कहलाने लायक कुछ नहीं था। उनके पास सिर्फ मेहनत-मजदूरी करने की क्षमता थी। उन्हें मेहनत मजदूरी करने की अपनी इस क्षमता यानी श्रमशक्ति को बेचकर ही अपनी गुजर-बसर करनी पड़ती थी। मिलों और कारखानों के मालिक उनकी इस मजबूरी का फायदा उठाते थे। सूर्योदय से सूर्यास्त तक परिश्रम करने के बाद थके-हारे, कालिख पुते, मैले-कुचेले इन लोगों की भटियारखानों में भीड़ लग जाती थी। वेश्यालयों में भरमार हो जाती थी। इस तरह इनका जीवन बंधे-बंधाये एक ढर्रे पर चलने लगा था, उनका जीवन मैल से लथपथ घृणित, असहनीय होता जाता था। उनके जीवन के सफर का वर्णन करते हुए एंगेल्स ने लिखा था, "चारों तरफ कूड़े-कर्कट और राख के ढेर बिखरे पड़े रहते हैं, दरवाजे के सामने खाली किये गए गंदे तरल पदार्थ बदबूदार जोहड़ों में जमा होते रहते हैं। सबसे गरीब, सबसे कम वेतन पाने वाले बदनसीब मजदूर यहीं के रहने वाले होते हैं। इसके अलावा उनके साथ रहते हैं चोर-उचक्के और वेश्याओं के शिकार लोग। वे थोड़े से स्थान में एक-दूसरे के साथ सट कर ठसाठस भरे रहते हैं। ... प्रतिदिन वे गहरे गढ्ढे में गिरते जाते हैं। वे तंगहाली और गन्दे व घटिया माहौल के अनैतिक प्रभाव का विरोध करने की क्षमता दिनो-दिन खोते जाते हैं।" (इंग्लैण्ड में मजदूर वर्ग की दशा, पृ. 59, अंग्रेजी संस्करण)

मिलों और कारखानों के साथ जुड़े इन लोगों को तत्कालीन यूरोप के ज्यादातर मानवतावादी दया की दृष्टि से देखा करते थे। वे उन्हें जनतांत्रिक व्यवस्था का मैल मानते थे। वे सोचते थे कि सामाजिक जीवन से इन सब मैले-कुचेले लोगों को हटा कर समाज को कैसे कलंक-मुक्त किया जाए, समाज को कैसे स्वस्थ-सुन्दर-स्वाभाविक बनाया जाए।

लेकिन सर्वोन्नत उत्पादन यंत्रों के साथ जुड़े इन कालिख पुते चेहरे वाले लोगों में ही कार्ल मार्क्स अनागत नई सभ्यता के सृष्टाओं को देख पाये थे। सामाजिक विकास के नियमों के क्षेत्र में द्वन्द्वात्मक विचारधारा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दिखाया था कि इस मजदूर वर्ग के हाथों में ही नई सभ्यता की सृष्टि की चाबी-कुँजी निहित है। ये चाहे कितने ही नासमझ, अनपढ़, इन्द्रियपरायण आदि लगते हों– यह इनका सही परिचय नहीं है। यह उन पर जबरन थोप दिया गया पूँजीवाद का अभिशाप मात्र है। यह मजदूर वर्ग संघर्ष के गतिपथ पर ही एक दिन उठ खड़ा होगा। नवनिर्मित ज्ञान के आधार पर खुद को विकसित करेगा। राजनैतिक चेतना से लैस होकर वर्ग संघर्ष का हथियार तैयार करेगा। उन्नत रूचि-संस्कृति के द्वारा खुद को बिल्कुल बदल डालेगा। पूँजीवाद को ध्वस्त कर सर्वहारा का अधिनायकत्व-समाजवाद कायम करेगा।

मार्क्स-एंगेल्स ने यह भी कहा था कि समाजवाद किसी आदमी की शुभ इच्छा का फल नहीं है। यह कोई कपोल-कल्पित चिंतन भी नहीं है। समाजवाद सामाजिक विकास के नियम की अवश्यम्भावी परिणति है। समाजवादी व्यवस्था की रचना हमारी इच्छा-अनिच्छा पर निर्भर नहीं करती। हम सामाजिक विकास की धारा को विज्ञान-सम्मत ढंग से समझ सकते हैं, उसका असली चरित्र समझ कर उसके विकास को तेज कर सकते हैं और समाज का क्रान्तिकारी रूपांतर करने के क्षेत्र में अपनी उपयुक्त भूमिका निभा सकते हैं। विज्ञान-सम्मत विश्लेषण के जरिए मार्क्स ने दिखाया था कि सभ्यता के प्रगति-पथ पर पूँजीवाद आज प्रधान बाधा बनकर खड़ा हो गया है। नतीजतन उसे क्रान्ति की चोट से हटाना पड़ेगा, इसे चलता कर देना होगा। क्रान्ति की इस अप्रतिरोध्य शक्ति को पूँजीवाद खुद अपने अंदर ही पैदा कर रहा है। उसकी कब्र खोदने वाली यह शक्ति है मजदूर वर्ग। पूँजीवाद के शोषण-जुल्म के हाथों से मानव-सभ्यता की रक्षा करते हुए बेरोकटोक विकास का द्वार खोल देने की जिम्मेदारी आज मजदूर वर्ग के कंधों पर आन पड़ी है। इतिहास द्वारा सौंपी गई यह जिम्मेदारी मजदूर वर्ग को निभानी होगी। मार्क्स ने यह भी दिखाया था कि पूँजीवादी व्यवस्था की मूल समस्या है–यहाँ उत्पादन का चरित्र सामाजिक है लेकिन उत्पादन के साधनों और उत्पादन पर मालिकाना व्यक्तिगत है। इस समस्या का वैज्ञानिक समाधान उत्पादन के साधनों पर सामाजिक मालिकाना कायम करना है। लेकिन यह सामाजिक मालिकाना कायम करने के क्षेत्र में पूँजीपति वर्ग जबरदस्त रुकावट है। इनकी इस रुकावट को पार करने के लिए चाहिए एक ऐसी सामाजिक शक्ति जो पूँजीपतियों की तमाम रुकावट को चूर-चूर करके समाज को आगे ले जा सके। मार्क्स ने कहा था कि मजदूर वर्ग ही है वह शक्ति जिसके नेतृत्व में अन्य सभी तबकों की मेहनतकश जनता संगठित होगी और पूँजीवाद को ध्वस्त करके समाजवाद कायम करेगी।

लेकिन पूँजीवाद अपने स्वाभाविक विकास के सर्वोच्च स्तर अर्थात् एकाधिकार और वित्तीय पूँजी वाले साम्राज्यवादी स्तर में पहुँचकर वह आज मरणासन्न हो गया है, सामाजिक प्रगति के रास्ते में यह जबरदस्त रोड़ा बन गया है। इन नयी

परिस्थितियों में, साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रान्ति के वर्तमान युग में मार्क्स की शिक्षा को और भी विकसित करते हुए कॉमरेड लेनिन ने रूस की सरजमीं पर प्रयोग किया। उनके नेतृत्व में रूस की सरजमीं पर – 7 नवम्बर 1917 को दुनिया की पहली समाजवादी क्रान्ति हुई थी–जो इतिहास में महान नवम्बर क्रान्ति के नाम से मशहूर है।

नरोद्निक चिन्तन के खिलाफ संघर्ष और रूस में मार्क्सवाद की स्थापना

नवम्बर क्रान्ति कोई अचानक घटित हो जाने वाली घटना नहीं थी। इस क्रान्ति के लिए रूस के मार्क्सवादी चिंतनकारों को लम्बा रास्ता पार करना पड़ा था। क्रान्ति-विरोधी कई भ्रान्त चिंतकों का चेहरा बेनकाब करते हुए उन्हें मजदूर वर्ग को आगे बढ़ने की राह रोशन करनी पड़ी थी। विचारधारात्मक रूप से मजबूत आधार पर उन्हें खड़ा होना पड़ा था। उन्नत मतादर्श से लैस मजदूर वर्ग और दूसरे मेहनतकश तबकों के लोगों को क्रान्ति का रास्ता साफ करने के लिए बे-झिझक जान कुर्बान करनी पड़ी थी। जेल, आजीवन कठोर कारावास की सजा, देश निकाला, फाँसी के तख्ते–कोई भी कुछ भी करके संघर्ष के रास्ते से इन्हें वापस हटा नहीं पाया था। उनकी बहादुरी की गौरवगाथा सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई है।

रूस में मार्क्सवाद का चिंतन लेकर सबसे पहले आये थे प्लेखानोव। शुरूआती दौर में प्लेखानोव नरोद्निक चिंतन से प्रभावित थे। जार के अत्याचार से वे देश छोड़ने को मजबूर हुए थे और विदेश में मार्क्सवाद के सम्पर्क में आकर उन्होंने नरोद्निक चिंतन को त्याग कर मार्क्सवाद को जीवन दर्शन के रूप में ग्रहण किया था। 1883 में जेनेवा शहर में उन्होंने 'मजदूर मुक्ति संघ' की स्थापना की थी।

'मजदूर मुक्ति संघ' कायम करने के बाद प्लेखानोव रूस की धरती पर मार्क्सवादी चिंतन का प्रचार-प्रसार करने में जुट गये थे। लेकिन इस काम में प्रधान बाधा थी नरोद्निक चिंतन का प्रबल प्रभाव। तत्कालीन प्रगतिशील मजदूरों और क्रान्तिकारी नौजवानों के बीच यह चिंतन खूब प्रचलित था। नरोद्निक मानते थे कि (1) किसान क्रान्ति की प्रधान शक्ति हैं। केवल किसान विद्रोह के द्वारा ही जारशाही को उखाड़ फेंका जाएगा। (2) रूस में पूँजीवाद एक आकस्मिक विषय है। वहाँ इसका कोई विकास नहीं होगा और इसलिए सर्वहारा वर्ग के विकास की भी वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। (3) सर्वहारा क्रान्ति में मजदूर वर्ग नेतृत्वकारी वर्ग नहीं होता, नतीजतन वे मजदूर वर्ग के बिना ही समाजवाद की सोचा करते थे। (4) वे मानते थे कि वर्ग-संघर्ष के नतीजे के तौर पर इतिहास नहीं रचा जाता है, बल्कि इतिहास रचा करते हैं कुछ वीर पुरुष। जनता इन वीरों का अनुसरण मात्र करती है।

इस विज्ञान-विरोधी चिंतन से रूस को मुक्त कर पाये बिना रूस की जनता को क्रान्ति के लायक तैयार करना और समाज को बदल डालना सम्भव नहीं होगा। सैद्धान्तिक क्षेत्र में यह काम उस समय का प्रधान काम था।

नरोद्निकों के इस चिंतन के खिलाफ प्लेखानोव ने कलम थामी थी। 'समाजवाद और राजनैतिक संघर्ष', 'हमारे मतभेद', 'इतिहास के प्रति अद्वैतवादी दृष्टिकोण का विकास' आदि अपने प्रख्यात ग्रंथों में उन्होंने नरोद्निक चिंतन को खोखला साबित किया था। उन्होंने कहा था, "दरअसल रूस पूँजीवादी विकास के रास्ते पर पहले ही चल पड़ा था। उसने तथ्य देकर यह साबित किया और बताया कि ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो उसे इस रास्ते से हटा सके। ... इस सहज सत्य को स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ... क्रान्तिकारियों का काम था कि पूँजीवाद के विकास

(शेष पृष्ठ 4 पर)

महान नवम्बर क्रान्ति ...

(पृष्ठ 3 का शेष)

ने जिस ताकतवर क्रान्तिकारी शक्ति को, यानी मजदूर वर्ग को जन्म दिया था, उसका समर्थन प्राप्त करें, उनकी वर्ग-चेतना को विकसित करें, उसे संगठित करें और उसकी अपनी मजदूर वर्ग की पार्टी बनाने में मदद करें।"

इसके अलावा प्लेखानोव ने यह भी कहा था कि यह बात सही है कि संख्या में मजदूर अभी भी कम हैं। लेकिन फिर भी वे ही प्रधान क्रान्तिकारी शक्ति हैं, सर्वोन्नत उत्पादन यंत्रों के साथ जुड़े होने के कारण यह मजदूर वर्ग महान भावी स्रष्टा है।

दूसरी ओर, संख्या में किसान काफी ज्यादा होने पर भी वे उत्पादन व्यवस्था में सबसे पिछड़ी हुई धारा हैं। इनके बीच फूट-बिखराव भी तीव्र है। खुद छोटी-छोटी जोत के मालिक होने के कारण वे मजदूर वर्ग की तरह संगठित शक्ति को जन्म नहीं दे सकेंगे।

नरोद्निकों के खिलाफ प्लेखानोव के संघर्ष के नतीजतन क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी हलकों में उनका प्रभाव लगभग खत्म हो गया था। इसके बाद नरोद्निकों को जड़ से उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी लेनिन ने ले ली थी।

लेनिन का जन्म 1870 में हुआ था। 1889 में उन्होंने कजान विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। लेकिन क्रान्तिकारी आन्दोलन में शामिल होने के कसूर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। 1893 में वे सेन्ट पिटर्सबर्ग चले गये। 1895 में लेनिन ने सेंट पिटर्सबर्ग के मजदूर सर्कल को एक संगठन में एकजुट किया। इस संगठन का नाम था 'मजदूर मुक्ति संघ'।

लेनिन के संचालन में 'मजदूर मुक्ति संघ' ने मजदूरों की आर्थिक मांगों को मनवाने के चल रहे संघर्ष के साथ जार-शासन के खिलाफ चल रहे राजनैतिक संघर्ष को एक सूत्र में पिरो दिया था। रूस में इसी संगठन ने सबसे पहले मजदूर आन्दोलन के साथ समाजवाद की एकता साधने की शुरूआत की थी। लेनिन ने कहा था, सेन्ट पिटर्सबर्ग के 'मजदूर मुक्ति संघ' का महत्व था मजदूर वर्ग के आन्दोलन की पृष्ठपोषकता में क्रान्तिकारी पार्टी का सूत्रपात।

नरोद्निकों के खिलाफ लेनिन ने करारी चोट की थी। 1894 में लेनिन ने एक ग्रंथ लिखा था, '"जनता के दोस्त" कौन हैं और वे सोशल डेमोक्रेटों के खिलाफ किस तरह लड़ाई लड़ते हैं'। इस ग्रन्थ में लेनिन ने नरोद्निकों का असली चेहरा बेनकाब कर दिया था। उन्होंने दिखाया था कि नरोद्निकों ने संघर्ष का रास्ता बहुत अर्सा पहले ही त्याग कर जार सरकार के साथ समझौते का रास्ता अख्तियार कर लिया है। वे अब अमीर किसानों की कृषि व्यवस्था की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और कुलकों के दोस्त हैं। लेनिन ने लिखा था, "वे महज यही सोचते हैं कि जार सरकार से अत्यंत भद्र ढंग से विनीत होकर अपील करने से ही सरकार सब ठीक कर देगी।" (व्हाट आर दि "फ्रेंड्स ऑफ पीपल", सं. रचनाएं, खंड 1, अंगेजी सं, पृ. 200)

उस समय भी सभी नरोद्निक रूस में पूँजीवाद का विकास असम्भव मानते थे। उनकी धारणा का खण्डन करते हुए लेनिन ने 'दि डेवलेपमेंट ऑफ केपिटलिज्म इन रशिया' (रूस में पूँजीवाद का विकास) ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ में रूस की अर्थव्यवस्था की बारीकी से समीक्षा करते हुए लेनिन ने रूस में वर्ग-विन्यास का विश्लेषण किया था और दिखाया था कि रूस की कृषि में पूँजीवाद का विकास हो चुका है और सर्वहारा वर्ग लगातर नेतृत्वकारी भूमिका ग्रहण करता जा रहा है। उन्होंने यह भी दिखाया कि "the strength of the proletariat in the process of history is immeasurably greater than its shape of the total population." (इतिहास के गतिपथ पर सर्वहारा वर्ग की शक्ति समग्र जनता के वे जितने फीसदी हिस्से हैं उसकी तुलना में अनगिनत गुना ज्यादा है) लेनिन के इन सब विश्लेषणों ने नरोद्निकों के कफन में आखिरी कील ठोक दी थी।

अर्थवादियों के खिलाफ संघर्ष

रूस में मिलें और कारखाने जितने विकसित होते जा रहे थे, मजदूर वर्ग की संख्या और शक्ति उतनी ही बढ़ती जा रही थी, मालिकों के खिलाफ मजदूर वर्ग का संघर्ष भी उतना ही जोरदार होता जा रहा था। बड़े-बड़े शहरों में मजदूरों में मालिकों के खिलाफ रोष फूट पड़ रहा था, वे हड़ताल कर रहे थे, एक साथ काम बन्द कर दे रहे थे। वे मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे, काम का समय बांधकर 8 घण्टे करने की मांग कर रहे थे, सेवा शर्तों यानी काम के हालातों को सुधारने के लिए आवाज बुलन्द कर रहे थे, वे अपने बच्चों की शिक्षा और इलाज का बेहतर इन्तजाम करने, इन्सानों के रहने लायक मकान देने की मांग कर रहे थे। लेकिन मजदूर का यह संघर्ष सुस्पष्ट तौर पर दो धाराओं में बंट गया था। एक धारा अर्थवादियों की धारा थी। अर्थवादियों का मानना था कि मजदूर केवल आर्थिक मांगों के लिए ही लड़ाई करेंगे, उनकी लड़ाई होगी केवल उनके नियोक्ताओं के खिलाफ। उनका लक्ष्य होगा केवल खुद की आर्थिक स्थिति के स्तर को ऊँचा उठाना-राजनैतिक संघर्ष करना मजदूर वर्ग का काम नहीं है, वह है उदार बुर्जुआ वर्ग का काम। मजदूर इस उदार बुर्जुआ वर्ग का समर्थन करेगा। 1899 में अर्थवादियों ने एक इस्तिहार छापा था। उसमें कहा गया था कि सर्वहाराओं की राजनैतिक पार्टी गठित करना और मजदूर वर्ग की अलहदा राजनैतिक मांगें उठाना गैर जरूरी है।

अर्थवादियों के इन सब वक्तव्यों का लेनिन ने तीव्र विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि आर्थिक मांगों की अदायगी की घेराबन्दी में ही मजदूर आन्दोलन को सीमित कर डालने का मायने हैं उनके वेतन की गुलामी के जीवन को परम मान लेना। उन्होंने यह भी कहा था कि मार्क्सवादी अपने क्रान्तिकारी संघर्ष में सुधारों के संघर्ष को भी इसके अंग के रूप में शामिल करते हैं। लेकिन सुधारों के लिए संघर्ष हमेशा गौण होता है-वह मूल राजनैतिक संघर्ष का सहायक संघर्ष मात्र होता है। इसलिए मजदूर आन्दोलन का मूल केन्द्र बिन्दु होगा सर्वहारा का राजनैतिक मुक्ति आन्दोलन। और इसके लिए मजदूर वर्ग की सही वर्ग चेतना होनी चाहिए। यह सही वर्ग चेतना, अर्थात् सही राजनैतिक चेतना कहने से हम क्या समझते हैं? लेनिन ने कहा था, "भले ही यह वर्ग प्रभावित क्यों न हो, लेकिन जब तक वह हर स्वेच्छाचार, दमन-उत्पीड़न, हिंसा और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ प्रतिवाद करने के लिए प्रशिक्षित न हो, ...जब तक मजदूर इसके बौद्धिक, नैतिक और राजनैतिक जीवन के सभी प्रगटीकरणों में दूसरे सभी सामाजिक वर्गों, यानी जनता के दूसरे-दूसरे तबकों का अवलोकन करने के लिए ठोस घटनाओं से, खासकर सामयिक या स्थानिक राजनैतिक तथ्यों व घटनाओं से सीख न ले सकें; जब तक वे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण व वस्तुनिष्ठ अनुमानों को व्यावहारिक क्षेत्र में इस्तेमाल करना न सीख लें, तब तक मजदूरों की वर्ग चेतना सही राजनैतिक चेतना नहीं हो सकती।" (सं. रचनाएं, खण्ड 5, अंग्रेजी संस्करण, पृ. 412)

लेकिन यह सही वर्ग चेतना, राजनैतिक चेतना क्या मजदूर वर्ग की आर्थिक मांगों को लेकर चलने वाले संघर्ष के जरिए अपने आप निर्मित हो जाएगी? इसके जवाब में लेनिन ने कहा था, "मजदूरों में राजनैतिक चेतना सिर्फ बाहर से ही, यानी सिर्फ आर्थिक संघर्ष के बाहर से ही, मजदूरों और मालिकों के सम्बन्धों के बाहर से ही लायी जा सकती है। राजसत्ता व सरकार के साथ सिर्फ समस्त वर्गों व तबकों के सम्बन्धों, सभी वर्गों के बीच अन्त:सम्बन्धों के क्षेत्र से ही यह ज्ञान हासिल किया जा सकता है। ... मजदूरों के अन्दर राजनैतिक चेतना देने के लिए सोशल डेमोक्रेटों (उस समय कम्युनिस्टों को सोशल डेमोक्रेट कहा जाता था) को अवश्य ही जनता के सभी तबकों में जाना होगा, सभी दिशाओं में अपनी वाहिनी की यूनिटों को भेजना होगा।" (वही, पृ. 422) इस तरह लेनिन ने मजदूर आन्दोलन में राजनैतिक चेतना के असली महत्व और उसके स्रोत के बारे में विज्ञान-सम्मत विश्लेषण रखते हुए मजदूर आन्दोलन को अर्थवादियों के प्रभाव से मुक्त किया था।

अर्थवादी मजदूर आन्दोलन में स्वत:स्फूर्तता के सिद्धान्त का प्रचार कर रहे थे। वे कह रहे थे कि सोशल डेमाक्रेटों को मजदूरों के चिंतन को समाजवादी चेतना के स्तर तक उन्नत नहीं करना चाहिए। बल्कि सोशल डेमाक्रेटों को आम लोगों के स्तर तक नीचे उतर आना चाहिए। मजदूर आन्दोलन में से जब तक मजदूर वर्ग अपने आप समाजवादी चेतना के स्तर पर नहीं पहुँच जाता, तब तक सोशल डेमोक्रेटों को इन्तजार करना चाहिए। लेनिन ने इस चिंतन पर करारी चोट की थी। उन्होंने कहा था कि स्वत:स्फूर्तता के सिद्धान्त का जयगान करने का मायने है चेतना के महत्व को गौण कर देना, मजदूर वर्ग को स्वत:स्फूर्त आन्दोलन के दुमछल्ले में तब्दील कर देना, उन्हें मौकापरस्ती के दलदल में डूबो देना।

लेनिन ने यह भी कहा था कि "क्रान्तिकारी सिद्धान्त के बिना कोई क्रान्तिकारी आन्दोलन नहीं हो सकता। ... सबसे आगे बढ़कर लड़ने वाली शक्ति की भूमिका केवल वही पार्टी अदा करती है जिसका पथप्रदर्शन सबसे उन्नत सिद्धान्त करता हो।" (सं.र., खण्ड 1 भाग 1, पृ. 183-84)

अर्थवादियों के प्रभाव से मजदूर आन्दोलन को मुक्त करने के क्षेत्र में लेनिन के इस संघर्ष का महत्व असीम है।

रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की दूसरी कांग्रेस

1898 में सेन्ट पिटर्सबर्ग, मास्को, कियेव-इनके संग्रामी संघों ने एकजुट होकर एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाने की कोशिश की थी। इस उद्देश्य से उन्होंने 1898 के मार्च महीने में मिनष्क शहर में पहली कांग्रेस बुलायी थी। कांग्रेस में मात्र 9 सदस्य उपस्थित थे। लेनिन उपस्थित नहीं हो पाये थे -वे उस समय साइबेरिया में निर्वासित थे। सन् 1900 के प्रथम चरण में लेनिन साइबेरिया से लौट आये थे। लेनिन ने तय किया कि रूस की सरजमीं पर जो सब छोटे-छोटे मार्क्सवादी स्टडी सर्कल हैं, उनके बीच चिंतन की भ्रम-भ्रातियों को दूर कर एकताबद्ध रूप देने के लिए एक गुप्त अखबार प्रकाशित करने की जरूरत है। लेकिन यह अखबार विदेश से प्रकाशित करना पड़ेगा-ताकि जार की गुप्तचर वाहिनी इस पत्रिका के प्रकाशन को बन्द न कर सके। विदेश में प्लेखानोव, ऐक्सेलरोद और जासूलिच के साथ चर्चा करने के बाद *'ईस्क्रा'* (जिसका अर्थ होता है चिंगारी) प्रकाशित करने का लेनिन ने इन्तजाम किया। सन् 1900 के दिसम्बर में महीने में इस्क्रा का पहला अंक प्रकाशित हुआ था।

रूसी क्रान्ति के इतिहास में ईस्क्रा का प्रकाशन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना थी। इस अखबार की स्थापना के महत्व के बारे में लेनिन ने लिखा था, "हमारे मतानुसार एक अखिल रूसी राजनैतिक अखबार का प्रकाशन हमारे काम की शुरूआत होगी, हमारे आकांक्षित संगठन की सृष्टि का पहला कदम होगा। सर्वोपरि, यह अखबार ही मुख्य सूत्र होगा-जिसके सहारे हम अपने संगठन को (अर्थात् एक क्रान्तिकारी संगठन को ...) अडिग भाव से विकसित कर सकेंगे तथा उसे अधिक गहरा और व्यापक बना सकेंगे। ...जनता के व्यापक हिस्सों के बीच राजनीति और समाजवाद के बारे में आग्रह जाग रहा है। एक अखबार हुए बिना इसका प्रचार और आन्दोलन का संचालन करना सम्भव नहीं है। (सं.रचनाएं, खण्ड 4, पृ. 110)

पार्टी की राजनैतिक, वैचारिक, सांगठनिक संहति का पथ तैयार कर देने में *'ईस्क्रा'* ने वास्तव में सारे रूस में राजनैतिक अखबार की भूमिका ही अदा की थी।

विदेश में और गुप्त रूप से रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की दूसरी कांग्रेस का अधिवेशन 1903 में 30 जुलाई को हुआ था। पहले ब्रूसेल्स में अधिवशन होने पर भी बाद में पुलिस के दबाव में कांग्रेस का अधिवेशन लंदन में स्थानान्तरित करना पड़ा था।

26 संगठनों के कुल 43 प्रतिनिधियों ने इस कांग्रेस में भाग लिया था। कांग्रेस का कार्यक्रम ग्रहण करने के सवाल पर प्रतिनिधियों में भारी मतभेद था। यह मतभेद 'सर्वहारा के अधिनायकत्व के सवाल को केन्द्र करके था। लेकिन काफी चर्चा-बहस, तर्क-वितर्क के बाद पार्टी के कार्यक्रम में 'सर्वहारा के अधिनायकत्व' के विषय को स्थान मिल गया था। लेकिन पार्टी के नियम-कानूनों सम्बन्धी प्रस्ताव के मसविदे को लेकर चर्चा से असली संघर्ष शुरू हुआ। पार्टी का सदस्य कौन हो सकता है, पार्टी संगठन की प्रकृति कैसी होगी-इसको लेकर जोरदार बहस छिड़ गई थी।

लेनिन ने कहा था कि पार्टी का कार्यक्रम जो मानकर चलेगा, पार्टी की जो आर्थिक सहायता करेगा और पार्टी के किसी न किसी संगठन के साथ जुड़ा रहकर काम करेगा, वही पार्टी का सदस्य हो सकता है। लेनिन के इस मत का समर्थन प्लेखानोव ने किया था।

दूसरी ओर, मार्तोव ने कहा था कि कार्यक्रम मान कर चलना और आर्थिक सहायता करना आवश्यक विषय हैं। लेकिन यह शर्त नहीं होनी चाहिए कि सभी को किसी न किसी संगठन के साथ जुड़ कर रहना होगा।

लेनिन के मतानुसार सर्वहारा वर्ग की पार्टी 'दुर्भेद्य दुर्ग' की तरह होनी चाहिए। संगठन में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकेगा। किसी को सदस्य पद पाना है तो किसी न किसी संगठन के तहत रह कर ही उसे मानकर चलना पड़ेगा। लेकिन मार्तोव ने ऐसे सब लोगों के लिए पार्टी का दरवाजा खोल देना चाहा जो क्रान्ति के प्रति सहानुभूति रखते हों भले ही ढुलमुल हों, जो पार्टी के तहत किसी न किसी संगठन में शामिल नहीं होना चाहते, पार्टी के अनुशासन को भी नहीं मानना चाहते, पार्टी काम में जिन सब

(शेष पृष्ठ 6 पर)

पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई पुलिस बर्बरता की निंदा

फीस बढ़ोतरी तुरंत वापस लेने की उठाई मांग

पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़ में की गई बेतहाशा फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आन्दोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस बर्बरता की छात्र संगठन एआईडीएसओ ने घोर निंदा की और फीस बढ़ोतरी तुरंत वापस लेने, घायल छात्रों को उचित मुआवजा देने, उनका मुफ्त इलाज करने, झूठे मुकदमे तुरंत वापस लेने और सभी छात्रों को बिना शर्त रिहा करने की मांग की। इसके अलावा यह भी मांग की गई कि बर्बर लाठीचार्ज में संलिप्त पुलिस अधिकारियों को उदाहरणमूलक सजा दी जाए।

प्रैस को जारी एक बयान में एआईडीएसओ के महासचिव कॉमरेड अशोक मिश्रा ने कहा कि यूनिवर्सिटी की सीनेट ने अपनी पिछली बैठक में शैक्षिक वर्ष 2017-18 के लिए फीस में 1100 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया था। बी.ए. और बी.कॉम. कार्सो के लिए लिए सालाना फीस 2200 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई। बी.फार्मा कोर्स की फीस 5000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 50,000 रुपये सालाना कर दी गई। एम.ए. (पत्रकारिता) कोर्स की फीस 5200 रुपये सालाना से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी के डेंटल कोर्स के लिए सालाना फीस 86,000 रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी गई। पिछले वर्ष भी विभिन्न कोर्सों के लिए परीक्षा फीस 500 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दी गई थी। इस अमानवीय फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे छात्रों को पुलिस के बर्बर हमले का सामना करना पड़ा। एक बार फिर फासीवादी कदम के हिस्से के तौर पर विरोध की आवाज का गला घोटने के लिए छात्रों पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया और 62 छात्रों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 124 ए लगायी गई। हालाँकि आन्दोलन के दबाव में देशद्रोह की धारा हटा ली गई। यहाँ तक कि छात्रों से भारी मात्रा में उगाहे गए पैसों से नियुक्त किये गए सुरक्षा गार्डों को भी छात्रों के जनवादी अधिकारों का हनन करने के लिए इस्तेमाल किया गया। कॉमरेड मिश्रा ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में यह फीस बढ़ोतरी शिक्षा के निजीकरण-व्यापरीकरण की नीति के स्वाभाविक परिणाम के सिवा और कुछ नहीं है जिस नीति को केन्द्र सरकार द्वारा निजीकरण-उदारीकरण और भूमण्डलीकरण की नीति अपनाये जाने के बाद और भी तेजी से लागू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केन्द्र व विभिन्न राज्य सरकारें शिक्षा बजट में कटौती कर रही हैं और संस्थाओं के लिए बहुत ही कम पैसा आवंटित कर रही हैं। यूजीसी केन्द्र सरकार के एजेण्ट की तरह काम कर रहा है। इसके अलावा यूजीसी की ग्रांट देने की क्षमता में कटौती की प्रक्रिया शुरू हो गई है और एक नई फंडिंग एजेंसी यानी हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी (एचईएफए) कायम की जा रही है जो उच्च शिक्षा के संस्थानों को कर्ज मुहैया कराएगी। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न संस्थानों में बेलगाम फीस बढ़ोतरी नियमित प्रक्रिया बन गई है। एक तरफ इसने यूनिवर्सिटियों को कारपोरेट घरानों के लिए लूट-खसोट का लाभप्रद क्षेत्र बना दिया है और दूसरी तरफ मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग से आने वाले छात्रों की बहुसंख्या पर कठोर प्रहार किया है और दरअसल उन्हें शिक्षा के दायरे से ही बाहर धकेल दिया है। इस विकट परिस्थिति में एआईडीएसओ छात्रों, अध्यापकों, तमाम शिक्षा प्रेमी और जनवाद पसंद लोगों से उपरोक्त मांगों के समर्थन में 15 अप्रैल को अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस के रूप में मनाने का आह्वान करता है और इस अन्याय के खिलाफ छात्र आन्दोलन को भरपूर समर्थन देने का आग्रह करता है।

एमडीयू के गेट पर छात्रों ने फूंका पुतला

रोहतक (हरियाणा) : 15 अप्रैल को एआईडीएसओ के कार्यकताओं ने एमडी यूनिवर्सिटी, रोहतक के गेट नं. 1 पर पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़ में छात्रों पर हुए पुलिस दमन के खिलाफ केन्द्र सरकार के एचआरडी मंत्रालय का पुतला दहन व विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने मदवि में पीने के साफ पानी की भी व्यवस्था करने की मांग की। प्रदर्शन में हरीश कुमार सैनी, अमित कुमार, राजेश, आशा, नवीन, विप्लव, सचिन, जसवंत, सुमित, सिकन्दर, रितेश आदि शामिल थे।

शिक्षा बचाओ सेमिनार

जमशेदपुर(झारखण्ड) : 11 अप्रैल को ऑल इण्डिया सेव एज्यकेशन कमेटी झारखण्ड राज्य शाखा की तरफ से यहां एक सेमिनार किया गया। विषय था 'वर्तमान में शैक्षणिक चुनौतियां और शिक्षक का दायित्व'। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रख्यात शिक्षाविद व पीयूसीएल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर विनय कंठ। मुख्य वक्ता सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया के हिन्दी के प्राध्यापक व लेखक डॉ. अनुज लुगुन। सभा की अध्यक्षता गणमान्य शिक्षाविद डॉ. सी भास्कर राव ने की। विषय प्रवेश ऑल इण्डिया सेव एज्यूकेशन कमेटी के झारखण्ड राज्य सचिव सुमित राय ने किया और मंच संचालन करीम सिटी कॉलेज के प्राध्यापक डॉ. सुभाष चन्द्र गुप्ता ने किया।

डॉ. अनुज लुगुन ने कहा कि चाहे झारखण्ड हो या केन्द्र की सरकार शिक्षा को हाशिए पर धकेलने की एक साजिश हो रही है। शिक्षा को बाजार के अंतर्गत लाया जा रहा है और शिक्षा अब खरीद-फरोख्त की वस्तु में तब्दील होती जा रही है। सरकार शिक्षा की जिम्मेदारी लेने में कोताही बरत रही है, आनाकानी कर रही है। इसके खिलाफ शिक्षा बचाओ आन्दोलन वक्त की जरूरत हे। प्रोफेसर विनय कंठ ने कहा कि आज पूरे देश भर में खतरनाक तरीके से शिक्षा को साम्प्रदायिक और जातिवादी दृष्टिकोण से रेजिर्मेंटिड किया जा रहा है जो बेहद चिंताजनक बात है। इसके खिलाफ सभी जनवाद पसंद प्रगतिशील लोगों को आगे आकर प्रतिरोध खड़ा करना चाहिए। धन्यवाद ज्ञापन शैलेन्द्र अस्थाना ने किया।

शिक्षा- विरोधी 'स्वायत्त कॉलेज स्कीम' के खिलाफ रोष प्रदर्शन

नई दिल्ली : हाल ही में यूजीसी द्वारा प्रस्तावित स्वायत्त कॉलेज स्कीम के खिलाफ एआईडीएसओ की दिल्ली राज्य कमेटी की ओर से 7 अप्रैल को छात्र रैली व सभा का आयोजन किया गया। इससे पूर्व इस कार्यक्रम की तैयारी के क्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय के छः प्रमुख कॉलेजों में व्यापक प्रचार अभियान चलाया गया। जहां न केवल छात्रों से बल्कि शिक्षकों से भी इस विषय पर भारी समर्थन प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की शुरूआत रैली से हुई, जो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय के गेट पर जाकर सभा में तब्दील हो गई।

सभा को संगठन की दिल्ली विश्वविद्यालय कमेटी के अध्यक्ष राहुल सरकार, सचिव सौम्या सामल के अलावा सुमन, अशरफ ने सम्बोधित किया। सभा में अतिथि वक्ता के रूप में डूटा के उपाध्यक्ष डॉ. रावत ने भी अपनी बात रखी। सभा के मुख्य वक्ता के रूप में संगठन के दिल्ली राज्य अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने अपने वक्तव्य में बताया कि यूजीसी द्वारा लाई जा रही स्वायत्त कॉलेज स्कीम कितना बड़ा धोखा है। असल में सरकार इसके माध्यम से शिक्षा के व्यापारीकरण के रास्ते खोल रही है। वह कॉलेज प्रशासन को इस स्कीम की आड़ में छात्रों से मनमानी फीस वसूलने की छूट दे रही है। इसमें सरकार की किसी भी प्रकार की कोई दखलअंदाजी नहीं होगी। अंत में उन्होंने छात्रों से सरकार की शिक्षा-विरोधी नीतियों के खिलाफ सशक्त आंदोलन निर्मित करने की अपील की।

दिल्ली : सभा को सम्बोधित करते हुए राहुल सरकार

सभा का संचालन संगठन की दिल्ली राज्य सचिव कॉ. श्रेया सिंह ने किया।

इससे पूर्व 19 मार्च को इसी स्वायत्त कॉलेज स्कीम के खिलाफ डूटा के आह्वान पर एक संयुक्त रैली व सभा का आयोजन किया गया था। जिसमें एआईडीएसओ ने बढ़चढ़कर भाग लिया। संगठन की ओर से संगठन के राज्य उपाध्यक्ष कॉ. राहुल सरकार ने सभा को सम्बोधित किया।

ज्वलंत मांगों को लेकर प्रखण्ड मुख्यालय पर प्रदर्शन

कांटी (बिहार) : बढ़ते अपराध एवं भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाने, सभी भूमिहीनों को 10 डी. वास की जमीन देने, दाखिल खारिज में व्याप्त घूसखोरी पर रोक लगाने, थर्मल से होने वाले प्रदूषण एवं पानी की समस्या को दूर करने, राशन-किरासन एवं पेनशन राशि का भुगतान करने सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर एसयूसीआई (सी) लोकल कमेटी, कांटी के नेतृत्व में सैकड़ों किसान-मजदूरों ने प्रखण्ड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल थी। गुदरी बाजार से जुलूस शुरू हुआ जो पुराना चौक होते हुए प्रखण्ड कार्यालय पर पहुंच कर सभा में तब्दील हो गया।

सभा को पार्टी की राज्य कमेटी के वरिष्ठ सदस्य कॉ. अशोक कुमार सिंह, जिला कमेटी सदस्य नरेश तारकेश्वर गिरि, उमेश महता, सहदेव पासवान, जगदीश साह, अमन कुमार, विश्वनाथ गुप्ता, मो. जाहिद आलम, रानी देवी, कुमोद राय, उदय झा, प्रेम कुमार राम, रंजीत कुमार, उमेश पटेल, परन मांझी आदि ने सम्बोधित किया।

सभा की अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. एच रहमानी ने की एवं संचालन लालबाबू राय ने कियां

कांटी प्रखण्ड मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के कार्यकर्ता

महान नवम्बर क्रान्ति ...

(पृष्ठ 4 का शेष)

दुख-तकलीफों और खतरों की सम्भावना है वे उन्हें भी उठाने को राजी नहीं। मार्तोवपंथियों ने तो प्रस्ताव भी रखा था कि किसी हड़ताली को भी सिर्फ नाम लिखकर पार्टी का सदस्य होने का अधिकार दे दिया जाये। नतीजतन समझा ही जा सकता है कि मार्तोव का मत मान लेने से तो पार्टी विभिन्न मतों के एक जमावड़े के लोगों की पंचमेल खिचड़ी हो जाएगी। इस तरह की पार्टी सर्वहारा वर्ग की क्रान्ति के कष्ट भरे कठोर संघर्ष के रास्ते पर नेतृत्व नहीं दे सकती।

खैर, जो भी हो, लेनिन और लेनिन के अनुगामियों की काफी कोशिशों के बावजूद दूसरी कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया। मार्तोव का प्रस्ताव पारित हो गया था। 28 वोट उनके पक्ष में और 22 वोट विरोध में पड़े थे। लेकिन पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के गठन के सवाल पर लेनिन को जीत प्राप्त हुई। लेनिन मानते थे कि दृढ़ताबद्ध, नीति-सिद्धान्तनिष्ठ क्रान्तिकारियों को लेकर ही केन्द्रीय कमेटी का गठन करना चाहिए। मार्तोव का धड़ा कोशिश कर रहा था कि ढुलमुल और मौकापरस्त तत्व केन्द्रीय कमेटी में चुने जायें। इस विषय में कांग्रेस के ज्यादातर सदस्यों ने ही लेनिन के मत का समर्थन किया था, उसी समय से उन्हें बोल्शेविक कहा जाने लगा था। (प्रसंगवश बोल्शेविक शब्द की उत्पत्ति बोल्शिनोष्तवो से हुई है जिसका मायने है बहुसंख्यक) विरोधियों को मेन्शेविक (अर्थात् अल्पसंख्यक) कहा गया था।

यहाँ एक बात और बताना जरूरी है। इस कांग्रेस में प्लेखानोव द्वारा विभिन्न सवालों पर लेनिन के मत का समर्थन किये जाने पर भी उनका समर्थन क्षणिक था। चिंतन की नाना भ्रम-भ्रान्तियों की वजह से उन्होंने बहुत जल्द ही मेनशेविकों के गुट में जाकर भीड़ बढ़ाई थी।

पहली रूसी क्रान्ति

1904 के जनवरी महीने में रूस-जापान युद्ध छिड़ गया था। जारशाही की कमर किस हद तक टूट चुकी थी यह जार की फौज की बार-बार हार से समझ लिया गया था। जारशाही के प्रति जन-आक्रोश और घृणा लगातार बढ़ती जा रही थी। लेनिन ने लिखा था कि पोर्ट आर्थर के पतन का मायने है निरंकुशता के पतन की शुरूआत।

जार सरकार ने युद्ध का इस्तेमाल क्रान्तियों को रोकने के लिए करना चाहा था। लेकिन उसका पासा उल्ट पड़ गया। युद्ध के नतीजतन जार के खिलाफ मानो समस्त रूस नफरत से उबल पड़ा था। सारे रूस में मजदूरों की हड़तालें मानो बारूद के विस्फोट की तरह होने लगी थी।

बोल्शेविकों की बाकू कमेटी के नेतृत्व में 1904 में बाकू शहर में मजदूरों की एक बहुत ही बड़ी और सुसंगठित हड़ताल हुई थी। तेल के कुओं के मजदूर इस हड़ताल में विजयी हुए थे। बाकू हड़ताल के जरिये ट्रांस काकेशिया और सारे रूस देश में क्रान्तिकारी जागरण की शुरूआत हुई थी। स्तालिन ने लिखा था, "सारे रूस भर में जनवरी और फरवरी महीने में जो शानदार संघर्ष चला था, बाकू हड़ताल उसी का संकेत थी।" 3 जनवरी 1905 में सेन्ट पिटर्सबर्ग के सबसे बड़े कारखाने पुतिलेव में हड़ताल शुरू हुई। यह हड़ताल चारों ओर फैलने लगी और सेन्ट पिटर्सबर्ग के दूसरे-दूसरे कारखाने भी इसमें शामिल होते गये। इस हड़ताल को भितरघात करके तोड़ देने के लिए जार सरकार ने गेपन नामक एक पादरी का इस्तेमाल किया। काफी पहले से ही पादरी गेपन जार सरकार के एक गुप्त अनुचर के तौर पर काम कर रहा था। जार सरकार की गोपनीय मदद लेकर गेपन ने 'रूसी कारखाना श्रमिक सभा' नामक एक यूनियन बनायी थी। सेन्ट पिटर्सबर्ग के चारों ओर इसकी शाखाएं थी। हड़ताल शुरू हो जाने के बाद गेपन ने मजदूरों के एक अधिवेशन में अपनी विश्वासघातक योजना पेश की। योजना यह थी कि 1 जनवरी को मजदूर एक जगह इकट्ठे होकर गिरजाघर का झण्डा और जार की तस्वीर हाथों में लेकर शान्तिपूर्ण ढंग से जुलूस निकालते हुए शीतकालीन महल की ओर जाएंगे और अपनी मांगों से सम्बन्धित ज्ञापन बादशाह को सौंपेंगे। बादशाह उनकी बात सुनेगा और उनकी मांगें पूरी कर देगा। बोल्शेविकों के प्रभाव से मांगपत्र में संविधान सभा बुलाना, कानून की नजर में सभी का समान अधिकार हो, राज्य और धार्मिक संस्थाओं को अलग-थलग करना, युद्ध का खात्मा, आठ घण्टे काम का समय तय करना, किसानों को जमीन देना आदि मांगें जोड़ देनी पड़ी थी।

बोल्शेविकों ने मजदूरों को समझाने की बार-बार कोशिश की थी कि जार से आवेदन-निवेदन करने का कोई लाभ नहीं होगा। बोल्शेविकों ने यह बात भी मजदूरों को बताने की बार-बार कोशिश की थी कि उन पर गोलियाँ भी चल सकती हैं। क्योंकि मजदूरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस समय भी यह विश्वास किया करता था कि जार सरकार उनकी मदद करेगी। इस जुलूस के खिलाफ होने पर भी बोल्शेविक पार्टी ने मजदूरों के साथ जुलूस में रहने का फैसला लिया था।

1905 में 9 जनवरी को सुबह पादरी गेपन के नेतृत्व में जुलूस शुरू हुआ। मजदूर सपरिवार जार की तस्वीर और गिरजाघर का झण्डा लिये हुए धार्मिक गीत-संगीत गाते हुए आगे बढ़ने लगे। जुलूस में लगभग 1 लाख 40 हजार से भी ज्यादा लोग शामिल थे।

जार सरकार ने गोलियों से जुलूस का स्वागत किया। एक हजार मजदूरों की जान गयी। काफी सारे बोल्शेविक कार्यकर्ता भी घायल हुए थे। सीने का खून बहाकर उन्होंने मजदूरों को पादरी गेपन के प्रभाव से मुक्त किया था। इतिहास में 9 जनवरी रक्त-रंजित रविवार के रूप में प्रसिद्ध हो गया था।

9 जनवरी के बाद से ही हड़तालों के साथ-साथ मजदूरों का क्रान्तिकारी संघर्ष और भी जोरदार हो गया था और उसने राजनैतिक रूप धारण कर लिया था। इन सभी हड़तालों ने पूरे देश को झकझोर दिया था और उसकी आँच देहाती इलाकों में भी जा पहुँची थी। विद्रोह में किसान भी शमिल हो गये थे। किसानों ने भूस्वामियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था, महलों और अनाज के गोदामों को आग के हवाले कर दिया था। जमींदार-सामंत गाँव छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगे थे। जार सरकार ने किसानों पर अत्याचार का स्टीम रोलर चलाया। लेकिन किसान-विद्रोह पर काबू नहीं पाया जा सका।

1905 में जून महीने में काला सागर में युद्धपोत पोतेमकिन ने बगावत का ऐलान कर दिया था। लेनिन ने इस बगावत पर बहुत ही महत्व दिया था। वे मानते थे कि इस आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण करना और मजदूरों, किसानों और स्थानीय सैनिकों के आन्दोलन के साथ तालमेल कायम करना बोल्शेविकों का परम कर्त्तव्य है। लेनिन ने कहा था कि मजदूरों की व्यापक राजनैतिक हड़तालें और जलसे-जुलूस, किसान आन्दोलन का प्रसार, जनता के साथ-साथ पुलिस और सेना के सिपाहियों के सशक्त संघर्ष और सब से अंत में पोतेमकिन युद्धपोत में बगावत यह साबित कर रही है कि जनता का सशस्त्र अभ्युत्थान लगातार परिपक्व हो उठा है।

रूस की इस पहली क्रान्ति (1905) का चरित्र था बुर्जुआ जनवादी क्रान्ति। सवाल उठा कि इस बुर्जुआ जनवादी क्रान्ति में सर्वहारा वर्ग की भूमिका क्या होगी? क्या वे बुर्जुआ वर्ग के नेतृत्व को मान लेकर उनके मददगार में तब्दील हो जायेंगे, या खुद ही आगे आकर क्रान्ति को नेतृत्व देंगे? इस सवाल पर तमाम भ्रम-भ्रान्तियों को दूर करते हुए लेनिन ने कहा था, "मार्क्सवाद सर्वहारा वर्ग को सिखाता है कि वह बुर्जुआ (पूँजीवादी) क्रान्ति से अलग न रहे, कि उसके प्रति उदासीन न रहे, क्रान्ति का नेतृत्व बुर्जुआ (पूँजीपति) वर्ग के हाथों में न जाने दे, बल्कि इसके विपरीत अत्यंत उत्साह के साथ उसमें भाग ले, सुसंगत सर्वहारा जनवाद के लिए, क्रान्ति को उसके अंत तक ले जाने के लिए, पूरी दृढ़ता के साथ लड़े।" (संकलित रचनाएं, खण्ड 1, भाग 2 हिन्दी पृ. 57)

अक्टूबर की राजनैतिक हड़ताल पूरे रूस में फैल गई थी। लगभग 10 लाख कारखाना मजदूर इस आम राजनैतिक हड़ताल में शामिल हुए थे, देश का पूरा जनजीवन ठप हो गया था, सरकार पंगू हो गई थी।

इसी समय रूस की सरजमीं पर एक असाधारण घटना घटी थी। जारशाही के खिलाफ संघर्ष की आग में मजदूरों की क्रान्तिकारी सृजनात्मक प्रतिभा के फलस्वरूप एक नया और शक्तिशाली संघर्ष का हथियार तैयार हुआ। संघर्ष के इस नये हथियार का नाम था—मजदूरों के प्रतिनिधियों की सोवियत।

सभी कारखानों से प्रतिनिधियों को लेकर मजदूर प्रतिनिधियों की ये सोवियतें गठित हुई थीं। ये मजदूर वर्ग के राजनैतिक संगठन का ऐसा एक रूप थीं जो पृथ्वी पर इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। ये सोवियतें जनता की अपनी खुद की सृजनात्मक शक्ति का नया क्रान्तिकारी रूप थीं। जारशाही के समस्त कायदे-कानूनों और फरमानों को अग्राह्य करके क्रान्तिकारी जनता ने ही इन सोवियतों की स्थापना की थी। ये सोवियतें जनता के क्रान्तिकारी संघर्ष को चलाने के राजनैतिक हथियार थी। इन सोवियतों का राजनैतिक तात्पर्य समझने में बोल्शेविकों ने भूल नहीं की। वे जानते थे कि ये सोवियतें जनता की राजनैतिक शक्ति का भ्रूण थी।

1905 में 26 अक्टूबर को सेन्ट पिटर्सबर्ग में सभी कारखानों के मजदूर प्रतिनिधियों की सोवियत का पहला अधिवेशन बैठा। सेन्ट पिटर्सबर्ग के बाद मास्को में मजदूर प्रतिनिधियों की सोवियत गठित हुई।

दु:खद होने पर भी यह बात सच है कि इन सोवियतों में मेन्शेविकों का बोलबाला था। इसलिए उनकी गलत योजना के चलते पहली रूसी क्रान्ति में सोवियतें जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती थी, वह भूमिका अदा नहीं कर पायी। नवम्बर 1905 में लेनिन रूस में वापस आये थे। उन्होंने सशस्त्र क्रान्ति के आयोजन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। ट्रांस काकेशिया में कॉमरेड स्तालिन पूरी पहलकदमी के साथ क्रान्ति की तैयारी का काम जारी रखे हुए थे। इसी समय दिसम्बर महीने में फिनलैण्ड के तामरफोर्स में बोल्शेविकों का सम्मेलन आयोजित हुआ था। यही लेनिन के साथ स्तालिन की पहली बार मुलाकात हुई थी।

20 दिसम्बर 1905 में मास्को की राजनैतिक हड़ताल शुरू हुई थी। लेकिन यह हड़ताल पूरे देश में नहीं फैलायी जा सकी थी। सेन्ट पिटर्सबर्ग से भी काफी समर्थन नहीं मिल पाया था। इसलिए शुरू से ही हड़ताल सफल होने की सम्भावना कम हो गई थी।

22 दिसम्बर को मास्को में बैरिकेड लड़ाई शुरू हो गई थी। नये दिन से कई हजार मजदूर पराक्रम के साथ लड़ाई लड़ने लगे थे। लेकिन मजदूरों की संख्या से जार के सैनिकों की संख्या कहीं ज्यादा थी। मास्को बोल्शेविक कमेटी के सभी नेता गिरफ्तार कर लिये गये थे। इसलिए सशस्त्र विद्रोह भिन्न-भिन्न इलाकों के साथ सम्पर्कहीन अभ्युत्थान में तब्दील हो गया था। विभिन्न इलाकों में मुख्यत: आत्मरक्षात्मक लड़ाई जारी थी। यही थी मास्को विद्रोह की प्रमुख कमजोरी और उसकी हार का प्रधान कारण। लेनिन ने कहा था, "हमें और भी दृढ़ता के साथ, शक्ति से, और हमलावर तरीके से हथियार उठाने चाहिए थे। हमें आम जनता को यह समझाना चाहिए था कि केवल शान्तिपूर्ण हड़ताल तक ही अपने आपको महदूद रखना नामुमकिन है, और निडर होकर और जम कर हथियारबन्द लड़ाई चलाना लाजिमी है।" (सं. रचनाएं, खण्ड 1, पृ. 446)

1905 को दिसम्बर विद्रोह इस क्रान्ति का चरम चरण हो गया था। जार के निरंकुश तंत्र ने क्रान्ति को कुचल डाला था। उसके बाद क्रान्तिकारी तेज में गिरावट आने लगी थी। क्रान्ति की लहर ठण्डी पड़ गयी थी।

1905 की क्रान्ति पराजित हो जाने के बाद शुरू हुआ स्तोलिपिन प्रतिक्रिया का युग। स्तोलिपिन जार सरकार का मंत्री था। उसकी पहलकदमी से सर्वत्र मजदूर वर्ग के राजनैतिक और आर्थिक संगठनों को ध्वस्त कर दिया गया था। जेलों, किलों और देश निकाले की जगहों पर क्रान्तिकारी नेताओं और कार्यकर्ताओं को ठूंस दिया गया था। असंख्य क्रान्तिकारियों को फांसी दी गयी थी। आन्दोलन और संघर्ष के जरिए मजदूर-किसानों ने जो अधिकार हासिल किये थे, वे सब छीन लिये गये थे। नये-नये दमनात्मक कानून लागू कर दिये गये थे।

क्रान्ति की हार का नतीजा स्तोलिपिन प्रतिक्रिया ही अकेला मामला नहीं था। क्रान्तिकारी पाँतों में भी टूटन और अध:पतन शुरू हो गया था। क्रान्ति जब लम्बे डग भरती हुई तेज रफ्तार से अग्रसर हो रही थी तब जो लोग क्रान्तिकारी आन्दोलन में शामिल हुए थे, उनमें से अनेक अब पार्टी छोड़ कर चले गये थे। फिर कोई-कोई खुले आम क्रान्ति के दुश्मन खेमे में भी शामिल हो गया था या कोई जारशाही के साथ मिलिभगत कर चैन से घर में रहने लगा था।

बोल्शेविकों के खिलाफ इस समय मेन्शेविकों ने अलग तरीके से प्रहार करना शुरू किया था। मेन्शेविक यह नहीं मानते थे कि क्रान्ति के प्रवाह में फिर ज्वार आ सकता है। वे मानते थे कि पराजय ही आखिरी हश्र है, रूस में क्रान्तिकारी शक्ति अब कभी आगे अपना सिर नहीं उठा पायेगी। इसलिए उन्होंने क्रान्तिकारी कार्यक्रम को त्याग देने की बात कही, सर्वहारा वर्ग की क्रान्तिकारी पार्टी को विसर्जित कर देने की मांग उठायी। इतिहास में ये इसीलिए विसर्जनवादी के

(शेष पृष्ठ 7 पर)

महान नवम्बर क्रान्ति ...

(पृष्ठ 6 का शेष)

तौर पर जाने जाते हैं।

मौकापरस्त विचारधारा के आविर्भाव के समय से ही लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने इन विसर्जनवादियों के खिलाफ बड़ा कठोर संघर्ष चलाया था। लेनिन ने कहा था कि पार्टी में उदार पूँजीपति वर्ग (लिबरल बुर्जुआ वर्ग) के दलाल हैं ये विसर्जनवादी।

पार्टी के इन दुर्दिनों में जनसाधारण के साथ जीवन्त सम्पर्क बनाये रखने की जरूरत से बोल्शेविक अपने काम करने के कौशल में महत्वपूर्ण परिवर्तन ले आये थे। बोल्शेविक ट्रेड यूनियनों और असहायों संतप्तों की कल्याण समितियों, मजदूरों की सहकारी समितियों, क्लबों, शिक्षा समितियों आदि कानून-सम्मत संस्थाओं को इस्तेमाल करने लगे थे। इस तरह जनसाधारण के साथ घुल-मिल कर रहते हुए बोल्शेविक जार सरकार की गलत नीतियों को बेनकाब कर दिया करते थे, मजदूरों को लामबन्द करते थे और किसानों को सर्वहारा वर्ग के पक्ष में खींच लाने की कोशिश करते थे। इस क्षेत्र में वे राष्ट्रीय निर्वाचित प्रतिनिधि सभा 'ड्यूमा' को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे। पार्टी के गैर-कानूनी संगठनों को अटूट रखते हुए कानूनी संगठनों को भी इस्तेमाल करने की यह दोहरी नीति अपनाने के फलस्वरूप बोल्शेविक फिर नये सिरे से शक्ति बटोरने के रास्ते पर आगे बढ़ सके थे।

क्रान्ति की हार के नतीजे के तौर पर प्रतिक्रिया ने एक अलग तरह के हमले के रूप में भी खुद को प्रकट किया। यह हमला दार्शनिक रूप से मार्क्सवाद पर हमले के जरिए आया। इन हमलावरों में शामिल थे बोग्दानोव, लूनाचारस्की, यूश्केविच, वैलेन्तिनोव आदि लेखक। इन्होंने मार्क्सवाद की दार्शनिक नींव पर, अर्थात् द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के मूल सिद्धान्त पर हमला बोला था। ये खुद के बारे में मार्क्सवादी होने का दावा करते थे। ये कहा करते थे कि मार्क्सवाद को सीमाबद्धता से मुक्त करके वे इसे और भी उन्नत करना चाहते हैं। यह खतरा छल-कपट भरा था। इसके फलस्वरूप पार्टी-पाँतों के आम सदस्यों के विपथगामी हो जाने की भरपूर सम्भावना थी। इसलिए इनके हर कथन का मुँहतोड़ जवाब देने की जरूरत थी। मार्क्सवादी छद्मवेश की आड़ में इनके भाववादी मुखौटे को बेनकाब कर देने, इनके क्रान्ति-विरोधी चरित्र को उजागर कर देने की जरूरत थी। लेनिन ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। 1909 में प्रकाशित हुआ था उनका प्रसिद्ध ग्रंथ 'मार्क्सवाद और अनुभवसिद्ध ओलाचना'। इस ग्रंथ में लेनिन ने दिखाया था, (1) दर्शन के क्षेत्र में आधुनिक संशोधनवादियों की प्रधान विशेषता है चतुराई के साथ मार्क्सवाद को ठुकराना, मार्क्सवाद के छद्मवेश में भौतिकवाद-विरोधी सिद्धान्तों का प्रचार करना।(2) रूस के माखपंथी (बोग्दानोव, बाजारोव आदि) भाववाद के जाल में जकड़े हुए पड़े हैं, भौतिकवाद को ठुकरा रहे हैं।(3) अनुभवसिद्ध आलोचकों की वर्ग भूमिका यह है कि वे आम तौर पर भौतिकवाद के खिलाफ हैं और विशेष तौर पर ऐतिहासिक भैतिकवाद के खिलाफ हैं।

रूसी क्रान्ति के इतिहास में लेनिन के इस ग्रंथ की भूमिका असीम है। स्तोलिपिन प्रतिक्रिया के युग में तरह-तरह के रंगों के संशोधनवादियों और दलत्यागियों के एक गुट के सम्मिलित हमलों के खिलाफ डट कर खड़े होकर उन्होंने मार्क्सवाद की प्राणसत्ता और मर्मवस्तु की रक्षा की थी।

स्तोलिपिन प्रतिक्रिया के युग में लेनिन की भूमिका का उल्लेख करते हुए परवर्ती काल में कॉमरेड स्तालिन ने कहा था, "1909-11 की बात है। तब प्रतिक्रान्ति की चोट से तहस-नहस पार्टी में टूटन की प्रक्रिया चल रही थी। पार्टी-अविश्वास के युग से गुजर रही थी। बड़ी भारी मात्रा में पार्टी छोड़ना जारी था। महज इतना ही नहीं कि बुद्धिजीवी लोग पार्टी को छोड़ते जा रहे थे, बल्कि यहाँ तक कि मजदूरों के एक हिस्से ने भी पार्टी छोड़ दी थी। यह पार्टी के विघटन और पतन का दौर था। तब गैर-कानूनी संगठनों की जरूरत की बात भी स्वीकार नहीं की गई थी। केवल मेन्शेविक ही नहीं, बल्कि बोल्शेविक भी विभिन्न गुटों, उपदलों और धाराओं में बंटे हुए थे। क्योंकि ज्यादातर ही मजदूर आन्दोलन से अलग-थलग पड़ गये थे। ....पार्टी के आदर्श को बुलन्द रखते हुए अतुलनीय धैर्य और असाधारण अध्यवसाय के साथ उन्होंने विक्षिप्त, छिन-भिन्न पार्टी को एकजुट किया था। मजदूर वर्ग के आन्दोलन में सभी पार्टी-विरोधी रुझानों के खिलाफ संघर्ष करते हुए बेमिसाल साहस और अध्यवसाय के साथ उन्होंने पार्टी के आदर्श की रक्षा की थी। (क्रमशः)

मेडिकल हैल्थ कैम्प लगाया

झज्जर (हरियाणा) : 8 अप्रैल को मेडिकल सर्विस सेण्टर, रोहतक यूनिट की तरफ से अच्छेज गांव में मेडिकल हैल्थ कैम्प लगाया गया। इसमें 250 से अधिक मरीजों की जांच की गई। इसमें खून की जांच, दांतों की जांच, गर्भवती महिलाओं की जांच, शूगर की जांच की गई। मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गई।

इस कैम्प में डॉ. विनोद, डॉ. परमार, डॉ. जितेन मुर्मू व डेंटल विभाग से डॉ. अनुराधा व खेमचंद ने मुख्य भूमिका निभाई। मेडिकल सर्विस सेण्टर के रोहतक के संयोजक डॉ. दीपक ने कैम्प आयोजित करने में सहयोग देने वालों का, किसान नेता करतार सिंह अच्छेज, जगदीश सरपंच, अजीत सरपंच पहाड़ीपुर, सुरेश व अन्यों का आभार व्यक्त किया। मेडिकल छात्रों डॉ. आशीष, बलराम, अंशुल, चिन्टू, प्रियंका सैनी, आसिफ, अनुज, ज्योति ने भी सहयोग दिया।

मारुति मजदूरों के साथ एकजुटता दिखाई

(पृष्ठ 1 का शेष)

मारुति-सुजुकी के मानेसर प्लांट में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक कम्पनी अधिकारी की मौत हो गई थी। इसके संदर्भ में 18 मार्च, 2017 को स्थानीय अदालत द्वारा 13 मजदूरों को आजीवन कारावास और अन्य 4 मजदूरों को 5 साल के कठोर कारावास और 13 मजदूरों को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। जबकि मेडिकल के आधार पर उक्त अधिकारी की मौत धुएं में दम घुटने की वजह से हुई थी। ये 13 मजदूर यूनियन के पदाधिकारी व सदस्य थे। इसीलिए उन्हें विक्टेमाइज किया गया। इस पूरे मामले में तत्कालीन राज्य सरकार का रुख मालिकपरस्ती करने और मजदूरों का भारी उत्पीड़न करवाने का रहा। मारुति की इस घटना के बहाने प्रबंधन ने 2500 कच्चे व पक्के कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया था। अदालत ने 117 मजदूरों को रिहा किया है जिन्होंने 4 साल जेल में बिताए हैं, जिससे यह साबित होता है कि मजदूरों व उनके परिवारों का भयंकर उत्पीड़न हुआ है।

सजायाफ्ता मजदूरों को तुरंत रिहा करने, बरी किये गए 117 मजदूरों सहित 18 अप्रैल 2012 से मारुति कम्पनी से निकाले गए 2500 के करीब स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखने व उन्हें इस बीच गुजरे समय का पूरा मुआवजा देने, घटना की हाई कोर्ट के पीठासीन जज से न्यायिक जाँच कराने, इतने बड़े पैमाने पर मजदूरों का रोजगार छीनने, मजदूरों का भारी उत्पीड़न करने में संलिप्त मारुति प्रबंधन व प्रशासनिक मशीनरी को कटघरे में खड़ा करने, ठेका प्रथा खत्म करने, ठेके पर लगे कर्मचारियों को नियमित करने और समान काम का समान वेतन के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना करने, श्रम अधिकारों पर हमले बंद हों, श्रम कानूनों में संशोधन वापस हों और श्रम कानूनों का उल्लघंन करने वालों से सख्ती से निपटने की माँग ज्ञापन में की गई।

नवम्बर क्रान्ति शताब्दी वर्ष के अवसर पर सभा

जयपुर (राज) : 16 अप्रैल को लुनियावास, जयपुर में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने महान नवम्बर क्रान्ति शताब्दी वर्ष पर सभा की। इसकी अध्यक्षता कॉमरेड राम दयाल चौधरी ने की। समारोह का उद्घाटन कॉमरेड शिवदास घोष पर रचित गान से हुआ।

मुख्य वक्ता पार्टी के केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड सत्यवान ने मौजूदा सड़ी-गली पूंजीवादी व्यवस्था से जनजीवन में उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए जोरदार आन्दोलन खड़ा करने और क्रान्तिकारी संगठन बनाने की जरूरत पर चर्चा की। उन्होंने आज के हालात में क्रान्ति की जरूरत भी दिखाई। अंत में रूस के उपन्यास 'जीवन की ओर' पर आधारित एक प्रेरणादायक नाटक का मंचन भी किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय गान के साथ सभा का समापन हुआ।

नाली व सड़क निर्माण नहीं किये जाने से जनता में भारी रोष

दुर्ग (छ.ग.) : स्थानीय सिकोला बस्ती में सिकोला तालाब के पास, सब्जी मंडी दीवार से लगे क्षेत्र में नाली, सड़क निर्माण की मांग को लेकर 10. अप्रैल को एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) द्वारा जनप्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस क्षेत्र में सड़क निर्माण नहीं होने से मोहल्लेवासी आवागमन की समस्या से जूझ रहे है। बरसात के दिनों में और भी विकट समस्या हो जाती है। पूरा मोहल्ला कीचड़ से भर जाता है जिससे छात्रों, बुजुर्गों, कामकाजी महिलाओं को भारी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है और कोई आपातकाल की स्थिति होने पर यह समस्या और भी बढ़ जाती है। मोहल्ले में नाली नहीं होने के चलते गंदे पानी की निकासी की बड़ी समस्या है जिससे स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। इसके चलते मोहल्लेवासियों में जबरदस्त रोष है।

पानी की किल्लत दूर करने की मांग उठी

दुर्ग (छ.ग.) : 10 अप्रैल को एस.यू.सी.आई.(सी) जिला समिति दुर्ग के नेतृत्व में डिपरा पारा वार्ड 39, तालाब पार गौरा चौरा मोहल्ले में व्याप्त पानी की भारी किल्लत की समस्या के समाधान को लेकर जनप्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि मोहल्ले में पानी की समस्या तत्काल हल की जाए, तालाब पार गौरा चौरा मोहल्ले की पाइप लाइन को मुख्य पाइप लाइन से जोड़ा जाए, तब तक टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाए, सार्वजनिक नलों की संख्या बढ़ाई जाए व घर-घर सरकारी नल लगाया जाए। ज्ञात हो कि मोहल्ले में पानी की समस्या को लेकर समाधान के लिए गर्मी शुरू होने के पहले दो बार जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जा चुका है लेकिन प्रशासन पानी की समस्या को नजरअंदाज कर सिर्फ आश्वासन देकर उदासीन बना हुआ है। इससे मोहल्लेवासियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन सौंपने वाली महिलाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पानी की समस्या का निराकरण एक हफ्तें में नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जायेगा।

भवन निर्माण कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन

महम (हरियाणा) : 6 मार्च को एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा का महम ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन स्थानीय विश्वकर्मा धर्मशाला में किया गया। इसकी अध्यक्षता रमेश कुमार भैणी चन्द्रपाल ने की। संचालन जगदीश चंद्र, जिला सचिव ने किया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता एआईयूटीयूसी के प्रांतीय प्रधान कॉमरेड सत्यवान थे। इसके बाद यूनियन नेताओं ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा।

3 अप्रैल को बहादुरगढ़ ब्लॉक का सम्मेलन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता एआईयूटीयूसी के प्रांतीय प्रधान कॉमरेड सत्यवान थे। संचालन जगदीश चंद्र, जिला सचिव ने किया।

8 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 Fortnightly , Date of Publication : April 20, 2017
सर्वहारा दृष्टिकोण
22 अप्रैल से 6 मई 2017

दिल्ली नगर निगम चुनाव में वामपंथी उम्मीदवारों को चुनें

दिल्ली नगर निगम चुनावों में वामपंथी उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील करते हुए वामपंथी पार्टियों की तरफ से 15 अप्रैल को जारी संयुक्त बयान मे कहा गया : सात वामपंथी पाटियों, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई(एमएल-लिबरेशन), एसयूसीआई(सी), एआईएफबी, आरएसपी और सीजीपीआई ने दिल्ली में आगामी तीनों दिल्ली नगर निगम चुनाव संयुक्त रूप से लड़ने का फैसला लिया है। वामपंथी पाटियों ने तीनों नगर निगम में कुल 62 उम्मीदवार खड़े किये हैं जिनमें सीपीआई के 14, सीपीएम के 16, सीपीआई(एमएल-लिबरेशन) के 13, एसयूसीआई(सी) के 2, एआईएफबी के 16 तथा सीजीपीआई के 1 उम्मीदवार हैं।

वामपंथी पाटियों का सुविचारित मत है कि दिल्ली में नगर निगमों द्वारा प्रदान की जाने वाली नागरिक सुविधाओं में चौतरफा व्याप्त संकट के लिए भारतीय एकाधिकारवादी पूंजीपति वर्ग की दो अति भरोसेमंद पार्टियाँ, बीजेपी और कांग्रेस जिम्मेदार हैं, जिसका मूल कारण नागरिक सुविधाओं के निजिकरण-व्यापारीकरण की प्रक्रिया में निहित है जिसे 1990 के दशक में कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया और बीजेपी द्वारा उसे और भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। इन दोनों पार्टियों की घोर जनविरोधी नीतियों से परेशान लोगों ने उम्मीद की थी कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनावों के पहले लोगों से जो वायदे किये थे वह उन्हें पूरा करेगी। जब लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी और भाजपा तथा कांग्रेस में कोई मौलिक अन्तर नहीं है, तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। कारपोरेट घरानों की स्वार्थ पूर्ति के लिए जिन नीतियों को कांग्रेस ने लागू किया, अब उन्हें और भी जोर शोर से बीजेपी तथा आम आदमी पार्टी द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी भी नागरिक सुविधाओं के निजीकरण-व्यावसायीकरण की प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है जो कि दिल्ली की आम जनता के हितों के शर्तिया विपरीत है।

सफाई कर्मचारियों, अध्यापकों, अस्पतालों के कर्मचारियों और एम.सी.डी. के तहत चलने वाले अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों की सेवाओं के व्यापक ठेकाकरण ने और कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन दिये जाने और उसकी अनुचित देरी से की जा रही अदायगी ने इन निकायों में न केवल कुप्रबंधन को पैदा किया है बल्कि व्यापक भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दिया है। इस वजह से स्वास्थ्य व स्वच्छता, शिक्षा, सीवेज, जल आपूर्ति, पार्कों के रख रखाव, कुत्तों और बंदरों के आतंक से निजात दिलाने, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया आदि बीमारियों की रोकथाम के ऐतियाती कदम उठाने जैसी सेवाओं में गिरावट आई है। पूंजीपति वर्ग की अति भरोसेमंद इन पार्टियों में से कोई भी पार्टी अनियमित/अनधिकृत कालोनियों को नियमित किये जाने के बारे में गंभीर नहीं है। वामपंथी पार्टियाँ इस बारे में बहुत ही चिंतित हैं कि बिना कोई समुचित वैकल्पिक व्यवस्था किये ही झुग्गी-झोपड़ी के बासिंदों को उजाड़ने की साजिश शासक पाटियाँ कर रही हैं। वृद्धावस्था पेंशनधारियों, विधवाओं और विकलांगों को दी जाने वाली पेंशन भी बंद कर दी गई है। इसके चलते ये लोग कंगाली और बदहाली का शिकार हो रहे हैं।

जहाँ ये तमाम पार्टियाँ जनजीवन से कोई सरोकार न रखने वाले मुद्दों को उठाकर लोगों का ध्यान भटकाने में प्रयासरत हैं, वहीं वामपंथी पार्टियाँ लोगों द्वारा उनके रोजमर्रा के जीवन में भुगते जा रहे मुद्दों पर धर्मनिरपेक्ष और जनवादी आन्दोलन गठित करने और उन्हें धर्म, सम्प्रदाय, जाति, क्षेत्रीय पहचान आदि से ऊपर उठकर संगठित करने का भरसक प्रयास कर रही हैं। तमाम नये चेहरों को टिकट देने के जरिये बीजेपी ने इस सच्चाई को खुद ही स्वीकार कर लिया है कि उनके तमाम मौजूदा पार्षद भ्रष्ट और बदनाम हैं। कांग्रेस और अन्यों दलों के साथ भी ऐसा ही मामला है जिनमें पुराने पार्षदों ने खुली बगावत का रास्ता अपना लिया है। अंतहीन और निरंतर गहराते संकट के इस युग में पूंजीवादी व्यवस्था एक भी ईमानदार और समर्पित नेता पैदा करने मे सक्षम नहीं हैं। वामपंथी पार्टियों का यह सुविचारित मत है कि केवल वाम, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी जन आंदोलन के जरिये ही समाज में नये और प्रगतिशील मूल्यबोधों को जन्म दिया जा सकता है। हमारा मानना है कि नगर निगमों के चुनाव भी इसी आन्दोलन का हिस्सा हैं।

नगर निगमों में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के खिलाफ तीनों नगर निगमों के तहत काम करने वाले ठेका मजदूरों और दिहाड़ी के लिये निगमों के तहत काम करने वाले तमाम मजदूरों को न्यूनतम वेतन की गारंटी के लिए संघर्ष की खातिर, दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सीवर और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिये और नगर निगमों को भूमाफिया और पानी माफिया, प्रोपर्टी डीलरों /बिल्डरों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए सातों वामपंथी पार्टियाँ दिल्ली के मतदाताओं में नये रुझान का सूत्रपात करें, जिनकी साफ-सुथरी छवि है और जो लोगों द्वारा भुगती जा रही नागरिक समस्याओं के समाधान के लिऐ धर्मनिपरेक्ष और जनवादी जन आन्दोलन विकसित करने में यकीन रखते हैं, उनको चुनें।

दिल्ली नगर निगम चुनावों में एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी ने नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के निम्नलिखित दो वार्डों से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है :

1. वार्ड संख्या 20 श्रद्धानंद कालोनी से कॉमरेड निर्मल कुमार
2. वार्ड संख्या 81 किशनगंज से कॉमरेड आशा रानी

धुबरी से फुलबारी के बीच रेल व सड़क पुल की मांग उठी

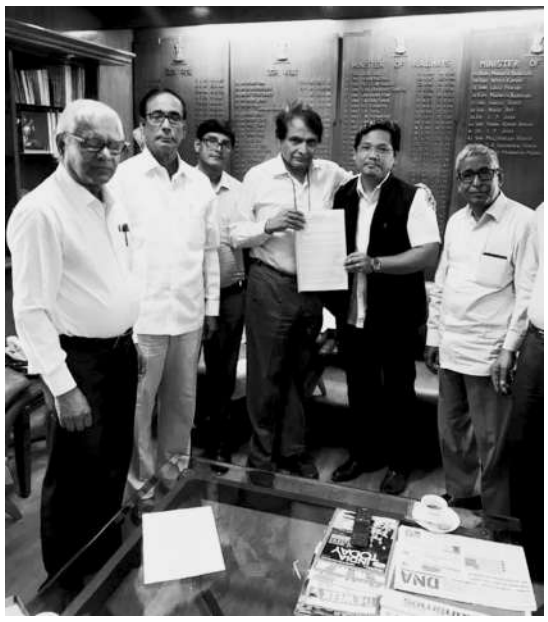

नई दिल्ली : 13 अप्रैल को आसाम की धुबरी फुलबारी रेल सह सड़क संग्राम कमेटी का एक प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली में केन्द्रीय रेल मंत्री से मिला और धुबरी से फुलबारी के बीच रेल और सड़क पुल बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

आई एआईयूटीयूसी ने किया हरियाणा रोडवेज कर्मियों की हड़ताल का समर्थन

बहादुरगढ़ (हरियाणा) : हरियाणा में प्राइवेट बसों को भारी संख्या में परमिट दिये जाने के सरकार के जनविरोधी फैसले के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए रोडवेज कर्मचारियों का एआईयूटीयूसी ने समर्थन किया। आन्दोलन के दबाव में सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। 13 अप्रैल को एआईयूटीयूसी और सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से छोटूराम धर्मशाला से बस अड्डे तक प्रदर्शन किया। इसमें एआईयूटीयूसी की तरफ से कॉमरेड जयकरण माण्डोठी, लालजी, सतीश कुमार, एसपी मौर्य, सीताराम, रामबड़ाई, संजीवन, प्रदीप, विजेन्द्र सहित कई कार्यकर्ताओं ने शिरकत की और हड़ताल का समर्थन किया। बिजली विभाग नगर पालिका, मजदूर कल्याण मंच, भवन निर्माण कारी मजदूर यूनियन, खेतमजदूर संगठन के मजदूर-कर्मचारियों ने भी रोडवेज कर्मियों के प्रति एकजुटता का इजहार

किया। 12 अप्रैल का जारी एक बयान में एआईयूटीयूसी के राज्य सचिव ने राज्य में बस रूटों के निजीकरण और पक्के कर्मचारियों से बहुत ही कम वेतन वाले डीसी रेटों पर कर्मचारी भर्ती की नीति वापस लेने की मांग की।

आंगनवाड़ी कर्मी आन्दोलन की राह पर

सोनीपत (हरियाणा) : एआईयूटीयूसी से सम्बन्धित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन, हरियाणा की सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं ने 8 अप्रैल को शानदार जुलूस निकाल कर अपना रोष प्रकट किया। जुलूस अम्बेडकर पार्क, बस अड्डे से शुरू हुआ और सैक्टर 15 स्थित महिला व बाल कल्याण विभाग की हरियाणा सरकार की मंत्री श्रीमती कविता जैन के निवास तक गया। वहां जुलूस के बाद मंत्री महोदया को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि संगठन की सोनीपत जिला कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती अनिता दहिया को नौकरी पर तुरंत बहाल किया जाए और 1482 आंगनवाड़ी कर्मियों को जारी किये गए कारण बताओ नोटिस तुरंत वापस लिये जाएं तथा उनको परेशान करना बंद किया जाए।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."

Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com
फोन नं. : 011-25726631, 9868350503